सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

वर्ष- 16 अंक - 36 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 19 नवंबर 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

टीटीडी बोर्ड ने लिए अहम फैसले: गैर-हिंदू कर्मचारी हटेंगे?, प्रसाद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी

तिरुपति। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड ने सोमवार को एक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने मीडिया से बात करते हुए इन फैसलों की जानकारी दी। नायडू ने बताया कि बोर्ड ने भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए इंतजार का समय कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने का फैसला लिया है। इस तकनीक के जरिए दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय करीब आधे घंटे घटकर 2-3 घंटे किया जाएगा।

इसके अलावा, तिरुपति के स्थानीय लोगों के लिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि हर महीने के पहले मंगलवार को उन्हें विशेष दर्शन की सुविधा दी जाएगी। बोर्ड ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मंदिर में काम कर रहे गैर-हिंदू कर्मचारियों के बारे में भी उचित निर्णय लेने को कहा है। नायडू ने बताया कि बोर्ड यह आंकलन करेगा कि मंदिर प्रशासन में कितने गैर-हिंदू कर्मचारी हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तिरुपति में 44 ऐसे कर्मचारी हैं, जो अन्य धर्मों के हैं। टीटीडी बोर्ड के प्रमुख ने कहा, हम राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे कि तिरुमाला मंदिर एक हिंदू धार्मिक संस्था है और इसमें गैर-हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार से निवेदन किया जाएगा कि या तो इन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाए या फिर इन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दिया जाए।

धान की कालाबाजारी, रायगढ़ में कोचियों के गोदाम से 225 बोरा धान जब्त

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने के साथ ही रायगढ़ जिले मे एक के बाद एक अवैध धान के मामले सामने आने लगे हैं। ताज़ा घटना क्रम उड़नदस्ता की टीम ने दो कोचियों के गोदाम में अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए 225 बोरा अवैध धान को जब्त किया है। उक्त मामला खरसिया विधानसभा क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ जिले में धान खरीदी की शुरुआत होते ही विभागीय टीम धान मंडियो तक अवैध धान न पहुंच सके। इसके लिए निगरानी बनाते हुए जिले में अवैध धान का कारोबार करने वाले लोगों पर नजरें जमाए हुए है। जिसके परिणाम स्वरुप उड़नदस्ता की टीम कोचिंयो पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है।

इसी बीच राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त उड़नदस्ता निगरानी को सूचना मिली थी कि रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देहजरी व डोमनारा में दो कोचियों के द्वारा गोदाम में अवैध रूप से धान भंडारण कर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर पहले विभागीय टीम ने देहजरी के रहने वाले रमेश कुमार गर्ग के गोदाम में छापा मारा। जहां उन्हें जांच के दौरान 25 बोरा में 10 क्विंटल अवैध धान मिला। इसके बाद टीम ने खरसिया क्षेत्र के ही डोमनारा में रहने वाले भविक्षण साव के गोदाम में भी छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान टीम को यहां 200 बोरी में 80 क्विंटल अवैध धान मिला।

देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना छत्तीसगढ़ का गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 'गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व' के रूप में एक नया टायगर रिजर्व मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव को धन्यवाद दिया है। यह टायगर रिजर्व देश का 56वां टायगर रिजर्व होगा। गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2829.387 वर्ग किलोमीटर होगा। इनमें आरक्षित वन 1254.586 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 1438.451 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्व क्षेत्र 136.35 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की जानकारी राष्ट्र को दी है। उन्होंने कहा कि भारत बाघ संरक्षण में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है, इसी क्रम में हमने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला को 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित

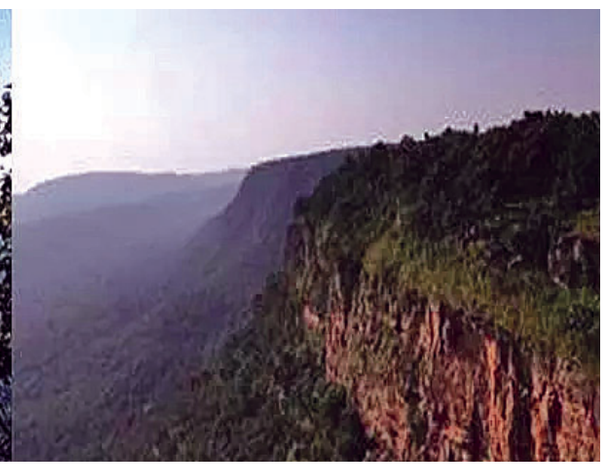

2021 में मिली थी मंजूरी

भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव योजना में परिकल्पित संरक्षण के लिए परिदृश्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नव अधिसूचित बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में संजय दुबरी बाघ अभयारण्य से सटा हुआ है, जो लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर का परिदृश्य परिसर बनाता है। इसके अलावा, यह अभयारण्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अक्टूबर, 2021 में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंजूरी दी थी।

जीव विविधता के लिए अनुकूल

छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित यह बाघ अभयारण्य विविध भूभागों, घने जंगलों, नदियों और झरनों से समृद्ध है, जो समृद्ध जीव विविधता के लिए अनुकूल हैं और इसमें बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास मौजूद हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से 365 अकशेरुकी और 388 कशेरुकी सहित कुल 753 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। अकशेरुकी जीवों का प्रतिनिधित्व ज्यादातर कीट वर्ग द्वारा किया जाता है। कशेरुकी जीवों में पक्षियों की 230 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 55 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें दोनों समूहों की कई संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।

किया है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अधिसूचना के साथ, छत्तीसगढ़ में अब 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं, जिससे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिल रही तकनीकी और वित्तीय सहायता से इस प्रजाति के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सलाह पर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया। कुल 2829.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बाघ अभयारण्य में 2049.2 वर्ग किलोमीटर का कोर/क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट शामिल है, जिसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, और इसका बफर क्षेत्र 780.15 वर्ग किलोमीटर का है। यह इसे आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाता है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश में अधिसूचित होने वाला 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है।

डबल मर्डर से दहली राजधानी, दो घंटे के भीतर दो युवकों की हत्या, गैंगवार में गई दोनों की जान

शराब दुकान से शुरू हुआ विवाद, एक की हत्या के बाद दूसरे को घर से किडनेप कर किया मर्डर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सोमवार की रात को दो युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया। आमा सिवनी के पास स्थित विदेशी शराब की दुकान के पास विवाद हुआ जिसमें एक गुट ने एक युवक की हत्या कर दी। जिसकी हत्या हुई उसका बदला लेने हत्या करने वाले युवक को घर से किडनेप कर उसे मार दिया गया। महज दो से तीन घंटों के भीतर यह सारा कांड हुआ। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सोमवार की रात लगभग 9 बजे सूचना मिली कि आमासिवनी के विदेशी शराब भट्टी में खाने-पीने के दौरान विवाद के कारण एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। जिसकी हत्या की गई उसका नाम रोहित सागर बताया गया और जिसने हत्या की उसका नाम हरीश साहू बताया गया। हरीश साहू ने अपने दो तीन साथियों के साथ रोहित की चाकू गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची ओर मृतक रोहित के शव को मेकाहरा पीएम के लिए भेजा।

इससे पहले की पुलिस हत्या के आरोपी हरीश साहू व उसके साथियों को गिरफ्तार करती उसकी भी हत्या हो गई। दरअसल जैसे ही रोहित सागर की हत्या की जानकारी उसके गुट के लोगों को लगी तो वे भड़क गए। रोहित सागर के साथी हरिश साहू के घर गए और उसे घसीटते हुए लगभग तीन किमी दूर ले गए। यहां पर रोहित सागर के साथियों ने हरिश को बुरी तरह मारा और चाकू गोदकर हत्या कर अपने साथी की हत्या का बदला ले लिया। यह पूरा घटना क्रम दो से तीन घंटों के भीतर हुआ। पुलिस ने मृतक हरिश साहू के शव को भी मेकाहरा भेज दिया।

दोनों के खिलाफ दर्ज हैं मामले

इस पूरे मामले में एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि मृतक राहित सागर व हरिश साहू पर पहले से कई केस दर्ज हैं। दोनों आदतन बदमाशों की श्रेणी में हैं। एएसपी ने बताया कि आपसी विवाद का मामला हैं और एक ही हत्या के बाद बदला लेने के लिए दूसरे की हत्या की गई। फ्लिहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है और कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है।

साइबर सेल के कर्मचारियों को 'कॉप ऑफद मंथ' अवार्ड

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में साइबर सेल के 4 कर्मचारियों को 'कॉप ऑफ द मंथ' का अवार्ड दिया गया है। चारों ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाकर 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आसनसोल, पश्चिम बंगाल से ठगी के मुख्य आरोपी को पकड़कर जीपीएम लाने वाली टीम को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

एसपी भावना गुप्ता ने गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीसार में हुए अंधे कत्ल के मामले को सुलझाने वाले साइबर सेल के प्रधान आरक्षक रवि त्रिपाठी, चौपाल कश्यप और आरक्षक हर्ष गहरवार और इंद्रपाल आर्मो को 'कॉप ऑफ द मंथ' के खिताब से नवाजा है। इन कर्मचारियों की तस्वीरें सभी थानों, चौकियों और कार्यालयों में पूरे माह के लिए प्रदर्शित की जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में नक्सल आपरेशन में मिल रही सफलता की पूरे देश में प्रशंसा : सीएम साय

■ बस्तर प्रवास के दौरान जवानों का उत्साह बढ़ाने सीएम अचानक पहुंचे सीआरपीएफ कैंप, जवानों के साथ किया रात्रि विश्राम

जगदलपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सीआरपीएफ के जवानों से कहा कि पिछले 11 महीनों के दौरान आप लोगों ने जिस तरह नक्सली आतंक को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। आप लोग परिवार से दूर रहकर और सुख-सुविधाओं को त्याग कर बस्तर के विकास में जो योगदान दे रहे हैं, उससे आप लोगों ने यहां के जनजातीय समुदायों के हृदय में अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए जगह बना ली है। श्री साय बस्तर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेडवा कैंप में जवानों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अचानक सीआरपीएफ कैंप पहुंचने पर आश्चर्यमिश्रित खुशी के साथ ही जवानों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्रीसाय ने सुरक्षा बलों के जवानों से आत्मीयतापूर्वक संवाद करते हुए कहा कि जब मैं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में चित्रकोट आया था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आप सब जवानों से मिलूं।

2026 तक नक्सलियों का समूल नष्ट करने का संकल्प

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में हमने नक्सलवाद को वर्ष 2026 तक समूल नष्ट करने का संकल्प लिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भी यही संदेश है। बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने अल्प अवधि में ही 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 740 से ज्यादा माओवादी कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे हिंसा त्याग कर लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। शासन ने हिंसा का त्याग करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए ऐसी नीति बनाई है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे।

पिछले 11 महीनों में छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जो सफलता मिली है, उसमें आप सभी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सभी के साहस को नमन करता हूं। नक्सल अभियान में आप सभी को जो सफलता मिल रही है, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जब भी मेरी मुलाकात होती है तो वे नक्सल अभियान में छत्तीसगढ़ को मिल रही सफलता का जिक्र जरूर करते हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह का नक्सल ऑपरेशन में सतत मार्गदर्शन और सहयोग मिलते रहा है।

50 हजार का लहंगा एक रुपया शगुन

श्रीकंचनपथ

शादियां भले ही पूरी दुनिया में होती हों पर सभी जगह इसके रीतिरिवाज अलग-अलग हैं। कुछ जगहों में तो शादी से ऐसी भी परम्पराएं जुड़ी हैं कि कभी-कभी जान पर बन आती है। भारत में भी विवाह की अलग-अलग परम्पराएं हैं। हिन्दी फिल्मों और टीवी सिरियलों ने अब शादियों को भड़कीला और खर्चीला भी बना दिया है। आम भारतीय मध्यमवर्गीय को एक बेटी का विवाह करवाना इतना भारी पड़ता है कि वह बेटी के जन्म के बाद से लेकर उसके विवाह तक सिर्फ तैयारियां ही करता रह जाता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो लड़कियों के हाथ पीले करना एक ऐसी समस्या बन गई कि वहां बेटियों का गर्भ में ही कत्ल होने लगा। लिंग अनुपात कुछ ऐसा बिगड़ा कि वहां के दूल्हों के लिए गरीब परिवारों की लड़कियां देश के विभिन्न भागों से खरीदी जाने लगीं। यहां तक कि पड़ोसी मुल्कों की गरीब लड़कियों को भी खरीदा जाने लगा। इसे रोकने कि दिशा में अब युवा जोड़े पहल करने लगे हैं। हरियाणा के सिरसा में रहने वाले दूल्हे ने राजस्थान में जाकर विवाह किया। शगुन के तौर पर केवल एक रुपया लिया। रिश्तेदारों से कोई शगुन लेने से वर-वधु ने साफइंकार कर दिया। इससे पहले हरियाणा के ही रेवाड़ी का निवासी एक फौजी भी एक रुपया शगुन लेकर विवाह कर चुका है। दान-दहेज जहां एक सामाजिक कुरीति है वहीं शादियों पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा वैवाहिक लिबास हैं। दुल्हन का एक लहंगा 50 हजार का। दूल्हे की शेरवानी भी 30-40 हजार की। लोग कहते हैं शादी एक ही बार होती है। अब नहीं पहने तो कब पहनेंगे। 4-5 लाख रुपए तो फोटो शूट और वीडियोग्राफी पर ही खर्च कर दिये जाते हैं। इसका एक बड़ा बाजार भी है। विवाह संस्कारों पर यह दिखावा भी भारी है।

संपादकीय

मुसीबत में मणिपुर, नियंत्रित होती हुई नहीं दिख रही स्थितियां

यह सामान्य बात नहीं कि मणिपुर बीते डेढ़ वर्ष से अराजकता और अशांति से जूझ रहा है। यदि वहां अशांति जारी रही तो अलगाववादी शक्तियों के साथ नशीले पदार्थों के कारोबार में लगे तत्वों का दुस्साहस तो बढ़ेगा ही सामाजिक वैमनस्य को दूर करने में भी मुश्किलें आएंगी। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होगी।

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक भी कि मणिपुर में स्थितियां नियंत्रित होती हुई नहीं दिख रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर एक बार फिर अप्रिय कारणों से चर्चा में है। कुछ समय पहले जब मणिपुर के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद-संपर्क का सिलसिला प्रारंभ किया गया था, तब यह आशा जगी थी कि राज्य में शांति बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन अचानक एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटीं, जिनसे हालात बेकाबू होते दिखने लगे।

मणिपुर के हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, इसका पता इससे चलता है कि वहां के कुछ इलाकों में अफस्पा को फिर से प्रभावी किया गया है। इसके साथ ही वहां अर्ध सैनिक बलों की पचास अतिरिक्त कंपनियों को भी भेजा जा रहा है। अशांति और उपद्रव को देखते हुए जिस तरह स्कूल-कालेज बंद करने और इंटरनेट सेवा बाधित करने की नौबत आ रही है, उससे यही प्रकट होता है कि इस राज्य को पटरी पर लाने में समय लग सकता है।

चूंकि मणिपुर में अशांति जारी रहते हुए अच्छा-खासा समय बीत गया है, इसलिए स्थितियां और अधिक जटिल हो गई हैं। पहले वहां केवल मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच ही अविश्वास की खाई गहरी और चौड़ी हुई, फिर नगा समुदाय भी अपनी शिकायतें लेकर सामने आ गया। चूंकि मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली ही सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वह इस राज्य में उन कारणों का तत्परता से निवारण करे, जिनके चलते वहां अस्थिरता और अशांति व्याप्त है। यदि मणिपुर के अशांत हालात देश को उतना अधिक प्रभावित नहीं करते, जितना अन्य किसी राज्य की बिगड़ती स्थितियां दिल्ली में चिंता और चर्चा का कारण बन जाती हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां के हालात सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता न दी जाए।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर के हालात की लगातार समीक्षा और निगरानी कर रहा है, क्योंकि प्रश्न यह है कि वहां स्थितियां सामान्य होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? केंद्र सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और म्यांमार से कुकी लोगों की घुसपैठ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ध्यान रहे कि खुद म्यांमार विद्रोहियों की गतिविधियों से अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में भारत सरकार को मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो समूचे राज्य में अफस्पा लागू करने से भी नहीं हिचकना चाहिए।

भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू मंदिर के पास हुई हिंसा को अस्वीकार्य बताया है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इसी से पूरी नहीं हो जाती। उन्हें इस शिकायत को दूर करना चाहिए कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण दिया गया है। कनाडा में सड़कों पर भारतीय मूल के लोग मजहबी पहचान के आधार पर लडऩे-भिडऩे लगें, तो समझा जा सकता है कि वहां स्थिति कितनी खतरनाक बन गई है। वैसे भी गुजरे सवा साल में भारत- कनाडा के कूटनीतिक संबंधों में बढ़ी टकराहट ने वहां रहने वाले लाखों भारतवंशियों को आशंकित कर रखा है। रविवार को इसमें नया अध्याय जुड़ा, जब ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थक सिख पहुंच गए, जब वहां भारतीय वाणिज्य दूतवास का शिविर लगा हुआ था। खालिस्तान समर्थकों की नारेबाजी पर हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति की, जिस पर झगड़ा शुरू हो गया। कनाडा पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो सभी हिंदू समुदाय के हैं।

इस घटनाक्रम ने भावनाओं में और उबाल ला दिया है। घटना पर पहले कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग, फिर भारतीय विदेश मंत्रालय, और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया। मोदी ने कहा- मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझ कर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने के कायरतापूर्ण प्रयास भी उतने ही भयावह हैं। इसके पहले भारतीय उच्चायोग ने भारत विरोधी तत्वों के हमले की निंदा की थी। स्पष्ट है, भारत सरकार ने घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। बहरहाल, प्रमुख मुद्दा यह है कि कनाडा में भारतवंशियों के बीच ऐसे विस्फोटक हालात क्यों बनते जा रहे हैं और अब समाधान क्या है? क्या कनाडावासी भारतीय मूल के लोगों में फिर से आपसी संवाद कायम करना संभव है, ताकि मतभेदों के बावजूद वे हिंसा का शिकार ना बनें? ऐसे प्रयासों में दोनों देशों की सरकारों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के पास हुई हिंसा को अस्वीकार्य बताते हुए शांति की अपील की है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इसी से पूरी नहीं हो जाती। उन्हें भारतवंशियों के मन में बैठी इस शिकायत का समाधान निकालना चाहिए कि उनकी सरकार कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देती है। उधर भारत सरकार से अपेक्षा है कि वह सभी समुदायों की तरफ बोले और कनाडा में सामुदायिक शांति के पक्ष में समझौताविहीन संदेश दे।

(आरएनएस)

नजरिया

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बुलडोजर के खौफ पर अंकुश

सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों पर सख्ती बरतने के बहाने उनके भवनों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर देने की कार्यवाही पर रोक लगाने का बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। न्यायालय का निर्देश है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी के घर, दफ्तर या दुकान पर मनमानी कार्यवाही कर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। इस तरह की कार्यवाही को अदालत ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे अराजकता का पर्याय माना है। शीर्ष न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति बीआर गवई एवं केवी विश्वनाथन ने फैसले में कहा है कि 'हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्यवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी आरोपित, यहां तक कि दोशी की संपत्ति भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं की जा सकती है।

प्रमोद भार्गव

कार्यपालिका, न्यायाधीश बनकर किसी को दंडित नहीं कर सकती। घर का होना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह आश्रयस्थल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के उपयोग में आता है। अतएव इस तरह की कार्यवाही अराजकता तो है ही, साथ ही संविधान में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है।' कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के घरों को तात्कालिक असंतोष को ठंडा करने के लिए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है।

इस सिलसिले में न्यायालय ने दिशा-निर्देश भी जारी किए है। हालांकि ये सब दिशा-निर्देश पहले से ही राज्य सरकारों की भू-राजस्व संहिता में शामिल हैं। लेकिन कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार अपने कानूनी एवं नैतिक दायित्व की अनदेखी कर सरकार की मंशा पूर्ति में लग जाते हैं। साफ है, यदि अधिकारियों को नेताओं की मंशा के अनुरूप ही काम करना है तो फिर उनके योग्य होने का क्या मतलब है? विधायिका से कार्यपालिका को इसीलिए पृथक रखा है कि वे किसी मंत्री या नेता की इच्छा पूर्ति की बजाय कानून का सम्मान करते हुए निर्णय लें।

किंतु अहम् पद पर बने रहने और कदाचरण से धन कमाने के मोह में वे अपनी योग्यता और कानूनी प्रक्रिया को खूंटी पर टांग कर अंधे होकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम देने में लग जाते हैं। जबकि ये अधिकारी भी कर्मचारी आचरण संहिता की शपथ लेकर अपने पद का दायित्व ग्रहण करते हैं। ऐसे में ये दावे थोते साबित होते हैं कि प्रजातांत्रिक गणतंत्र में जनता को राजनैतिक स्वतंत्रता और विधि सम्मत मौलिक अधिकार दिलाने का काम कार्यपालिका का है।

जबकि हकीकत यह है कि आपातकाल के बाद से विधायिका और कार्यपालिका का कुछ ऐसा गठजोड़ बनता चला गया कि जनमत की ताकत रखने वाली जनता, एक नए तरह की परतंत्रता की षिकार होती चली गई। भारत में यह परतंत्रता अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराने और बुलडोजर न्याय में पिछले कुछ वर्शों से खूब देखने में आ रही है।

इसीलिए अदालत ने दिए निर्देश में कहा है कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले 15 दिन का नोटिस और आरोपी को सुनने का मौका जरूर देना चाहिए। ये प्रावधान पहले से ही राज्यों की भू-राजस्व संहिताओं में है। इस संदर्भ में होता यह है कि तहसील अदालतें पिछली तारीख में नोटिस निकालने और उसे प्रभावित पक्षकार के घर पर चिपकाने की कार्यवाही तहसील दस्तावेजों में दिखा देते हैं। तहसील और अनुविभागीय न्यायालयों का हाल यह है कि कंप्यूटरीकरण हो जाने के बाद भी इन अदालतों में विचाराधीन मामलों का तारीखवार दस्तावेजीकरण नहीं है।

इसलिए जो राजस्व अदालतें कहती हैं, उसे ही ईश्वर की वाणी मानने पर पक्षकार को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि इस फैसले में यह स्पश्ट कर दिया है कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन और निकायों के लगभग सभी अधिकारी शामिल होंगे। मसलन अब कोई एकाधिकारी फैसला लेकर किसी के घर को नहीं तोड़ पाएगा। इससे यह फिलहाल लग तो रहा है कि मनमाने आदेष का क्रियान्वयन नहीं होगा। वाकई ऐसा होता है तो राज्य सरकारों के मुखियाओं के निरंकुश आचरण पर अंकुश लगेगा।

लेकिन देखने में आता है कि उन मकानों को भी ध्वस्त किया गया है, जिनके पास भूखंड की रजिस्ट्री होने के साथ निकाय प्रशासन की भवन निर्माण की अनुमतियां भी हैं। भवन मालिक के पास बिजली और नल के कनेक्शन तो हैं ही वह सालों से नगर पालिका या नगर निगम में संपत्ति कर भी जमा कर रहा है। यहां तक की देखने में आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी निर्मित घरों को वन भूमि पर निर्मित होना बताकर मध्यप्रदेश में तोड़ा गया है। यहां सवाल उठता है कि आखिर यह कौन तय करेगा कि भूमि वन विभाग की है या राजस्व की? इस बाबत यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई मकान सरकारी भूमि पर बनाया गया है तो उस पर निर्माण के दौरान ही कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? जबकि पटवारी और निकाय कार्यालयों के पास भूमि के मूल दस्तावेज होते हैं। यदि इस फैसले में जिम्मेबार अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान कर दिया जाए तो सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान बनाने का काम आरंभ ही नहीं होगा। इस सिलसिले में सच्चाई यह है कि जब सरकारी भूमि पर मकान बनता है तो जिम्मेदार कर्मचारी पैसा लेकर आंख मूंद लेते हैं। ध्वस्तीकरण के सिलसिले में यह भी विचारणीय बिंदु है कि अनेक मकान किसी एक अपराधी की संपत्ति नहीं होती है। उसके भाई-बहन और माता-पिता भी उस संपत्ति के वैध हिस्सेदार होते हैं। ऐसे में बलात्कारी जैसे अपराधी के साथ-साथ परिजन भी निर्दोश होते हुए दंड में भागीदार हो जाते है।

हालांकि अदालत ने साफ किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया पूरी करके की जा सकती है। यानी अनादिकृत निर्माण के मालिक को नोटिस देकर और उसे सुनकर बुलडोजर कार्यवाही का फैसला राजस्व अधिकारी दे सकते हैं। वैसे भी यह जरूरी है कि जो पेषेवर अपराधी खौफ दिखाकर सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर लेते हैं वे इस कार्यवाही से बचने का मार्ग न निकाल लें। ऐसे अपराधियों को जब संवैधानिक-राजनीतिक सुरक्षा कवच मिल जाता है तो अपराध की भूमिका उनके राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य के विस्तार का कारण बनते जाते हैं। यह सिलसिला तब और निष्ठुर एवं हिंसक हो जाता है, जब पुलिस तो पुलिस अदालत के न्यायाधीश भी ऐसे दुर्दांत अपराधी के मामले की सुनवाई से इंकार कर देते हैं। ऐसे लोगों को राजनेता एवं राजनीतिक दल न केवल संरक्षण देते हैं, बल्कि उसे विधानसभा या लोकसभा का टिकट देकर महिमामंडन भी करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के बहू व धनबलि अतीक अहमद के सिलसिले में यही सब देखने में आ चुका है। बेखौफहोकर उसने प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल समेत दो पुलिसकर्मियों की सरेआम हत्या करा दी थी। ये हत्यारे कानून व्यवस्था से इतने निश्चित रहते हैं कि चेहरे को ढकने की बजाय खुला रखते हैं, जिससे उनका खौफ कायम हो जाए कि ये हत्यारे कौन हैं? ऐसे व्यक्ति के बाबत जब न्याय व्यवस्था के संवैधानिक अंग पुलिस, न्यायालय और वकील कानून के राज को अंजाम तक पहुंचाने में असफल दिखे तो तीन युवकों ने एकाएक पत्रकार के भेष में अवतरित होकर अतीक और अशरफका काम तमाम कर दिया था।

न्यायिक सिद्धांत का तकाजा तो यही है कि एक तो अपराधी को समय पर ऐसी सजा मिले, जो फरियादी को न्याय लगे? लेकिन दुर्भाग्य से अतीक और उसके गिरोह को न तो समय पर सजा मिल पाई और न ही धन-संपत्ति कमाने की उसकी हवस पर अंकुश लग पाया। बल्कि इसके उलट वह पांच बार विधायक और एक बार सांसद बनकर अपराधी होने के बावजूद कानून के दायरे से बाहर रहा। जब ऐसे लोग निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाते हैं तो इनकी अनैतिक महत्वाकांक्षाएं और परवान चढ़ने लगती हैं। अपनी राजनीतिक इस छवि को ये दानदाता बनकर और अधिक भुनाने में लग जाते हैं। अतएव अपनी जाति और धर्म के गरीब लोगों की धर्म के नाम पर मदद कर फरिश्ते की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे ही उपकृत लोग इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इनकी जीत में निरंतर भागीदार बने रहते हैं। यह स्थिति न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने की बजाय, उसे खूंटी पर टांग देने का काम करती है। अतीक के साथ यही हुआ और वह क्षेत्रीय खतरे के साथ पाकिस्तानी आतंकवादियों से हाथ मिलाकर राष्ट्रीय खतरे की जद में भी आ गया था। शायद इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 95 पृष्ठ के इस फैसले में संविधान के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत और अभियुक्त के कानूनी व संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर जोर दिया है।

(ये लेखक के विचार हैं)

जलवायु और स्वास्थ्य नीतियों में तारतम्य का वक्त

दिनेश सी. शर्मा

अजरबैजान के बाकू में जलवायु वार्ता का वार्षिक दौर खतरे की घंटी के साथ शुरू हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपने वार्षिक आकलन में बताया है कि 2024 सबसे गर्म साल रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जिसमें जनवरी और सितंबर के बीच वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का पारा औद्योगीकरण से पहले रहे स्तर से लगभग 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक के आसपास मंडराता रहा। यह एक गंभीर खतरा है क्योंकि यह इजाफा उस 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम सीमा से ऊपर है, जिसे वैज्ञानिकों ने तय किया था और विश्व समुदाय ने उत्सर्जन में कमी लाकर इसको इस हद से नीचा रखने के लिए सहमति बनाई थी।

पेरिस समझौते का लक्ष्य औद्योगीकरण से पहले रहे स्तर की तुलना में धरती की सतह के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दीर्घकाल में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना था। जबकि इस वर्ष ला नीना प्रभाव के कारण गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड घनत्व निरंतर बढ़ रहा है जो तापमान वृद्धि का कारण बनती है।

तापमान वृद्धि से अतिवृष्टि और बाढ़, तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जानलेवा गर्मी, सूखा और जंगल की आग जैसे भयावह परिणामों के अलावा अनेक गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने व्याख्या की है: 'जलवायु आपदा स्वास्थ्य को नुकसान, असमानता में बढ़ोतरी और सतत विकास को हानि पहुंचा रही है, यह शांति की नींव को भी हिला रही है'। फंड, उपायों पर अमल और जलवायु वार्ताओं के परिणाम चाहे जो भी हों, दुनिया के सामने यह संकट मुंह बाए खड़ा है।

जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव व्यापक होता है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर हालिया रिपोर्ट 'द लैंसेट काउंटडाउन' बताती है:' हर देश में अब लोगों को अपने स्वास्थ्य और अस्तित्व पर बने खतरे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जलवायु संकट बढ़ रहे हैं'। सेहत पर प्रभाव डालने वाले कारकों में अब बढ़ती गर्मी प्रमुख वजह है, वर्ष 2023 में लोगों को औसतन 50 से अधिक दिनों तक लगातार प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ी, जबकि मौसम में आए बदलावों से पहले ऐसा नहीं होता था। इसके परिणामवश 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में जितने लोगों की मौतें हुई, वे 1990 के दशक के औसत से 167 प्रतिशत अधिक हैं। सर्वेक्षण में पाया कि 31 देशों ने कम-से-कम 100 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बनी गर्मी भुगती, जलवायु परिवर्तन के बिना ऐसा होने की उम्मीद न होती।

गर्मी के असर से शारीरिक गतिविधि और नींद की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे शारीरिक-मानसिक सेहत प्रभावित हो रही है। जो कर्मचारी खुले में या गैर-ठंडे बाहरी वातावरण में काम करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है और उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है। यह बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि विश्व स्तर पर लगभग 1.6 बिलियन लोग यानि कामकाजी आयु वर्ग की 25.9 प्रतिशत हिस्सा खुले में काम करता है। इसमें कृषि मज़दूर, विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्यरत और अनौपचारिक क्षेत्र में लगे लोग शामिल हैं।

स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का अन्य बड़ा असर यह होगा कि इससे जल-जनित, मच्छर-जनित, खानपान-जनित और वायु-जनित रोगों का प्रसार बढ़ने का खतरा है। बढ़ता तापमान, अतिशयी बारिश एवं सूखा, भूमि उपयोग में बदलाव और मानवीय गतिविधियां इस जोखिम में इजाफा करते हैं। उदाहरणार्थ पिछले 20 सालों में विश्व में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। 2023 में, एडीज एजिप्टी जैसे मच्छर का और अधिक इलाकों में फैलाव होने के कारण दुनियाभर में डेंगू के लगभग पचास लाख मामले सामने आए। तापमान वृद्धि के साथ हाल के दशकों में मलेरिया फैलने वाली अवधि भी बढ़ी है। दुनिया का 17 प्रतिशत अतिरिक्त भूभाग पी-फाल्सीपेरम जैसे मलेरिया परजीवियों के फलने-फूलने के अनुकूल हो गया है। जलाशयों के तापमान और लवणता में परिवर्तन के चलते जल जनित रोगों का संक्रमण अधिक फैल रहा है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन धीमा करने को निर्णायक कदम उठाने पर राजनेताओं और नीति निर्माताओं में आम सहमति बनने का दुनिया अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती। वार्षिक जलवायु परिवर्तन वार्ताएं अपने-अपने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित रखने के प्रयास बनकर रह गई हैं, और ऐसे पैंतरे अपनाए जाते हैं जिससे काम जल्दी होने की बजाय लटका रहे। इसलिए रास्ता यही कि लचीला जलवायु संबंधी तंत्र बने और उस पर अमल हो। हालांकि यह करना भी एक चुनौती है, उदाहरणार्थ, एयर-कंडीशनिंग जैसा उपाय अपनाना गर्मी के बढ़ते प्रकोप का स्थायी हल नहीं। यह महंगा व ऊर्जा की भारी खपत करने वाला है ,गर्मी के उत्सर्जन में योगदान करता है। इससे शहरी क्षेत्रों में, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में एयर-कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग से बना 'हीट आइलैंड' बढ़ता है। इसलिए, हमें अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ नवीकरणीय कम ऊर्जा खपत वाली शीतलन तकनीकों द्वारा संचालित एयर-कंडीशनिंग चाहिये।

डेंगू जैसी चुनौतियों के लिए, हमें जोखिम कम करने, एकीकृत मच्छर नियंत्रण उपायों और स्वास्थ्य प्रणालियों को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने पर जोर देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अपने उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। वर्तमान में, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा 5 प्रतिशत है। डब्ल्यूएचओ ने कॉप-29 सम्मेलन से पहले जारी की रिपोर्ट में बताया है कि स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए शहरों पर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी नीतियां कुछ ऐसी बनाई जाती हैं जिनका असर वायु गुणवत्ता, परिवहन, ऊर्जा उपयोग, शहरी डिज़ाइन, हरित क्षेत्र, आवास और भोजन की पहुंच पर होता है और यह आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए, कम कार्बन और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों वाले बदलाव लाने में देरी मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि है।

स्वास्थ्य पर जलवायु बदलावों का असर कम करने वाले तमाम उपायों पर काम करने की गाड़ी आखिर में आकर नई व्यवस्था और बेहतर विकल्प अपनाने पर होने वाले खर्च पर आकर अटक जाती है। इस हेतु अरबों डॉलर का अतिरिक्त फंड, जिसे देने का विकसित राष्ट्रों ने वादा किया था, शायद ही कभी पूरा हुआ हो। जलवायु सुधार फंड जुटाना एक जटिल मुद्दा है, उम्मीद करें कि बाकू में इस पर सार्थक प्रगति हो पाएगी। हालांकि, यह लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्राजील सहित शीर्ष विश्व नेताओं ने वार्ता के शिखर सम्मेलन वाले सत्र में भाग न लेने का फैसला किया है।

जैसा कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जलवायु-फंड अंततः स्वास्थ्य-फंड है। जहां एक और जलवायु कार्रवाई के लिए धन का इंतजाम मानव स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए जरूरी प्रणालियों को बचाने में मदद कर सकता है वहीं स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभावों को कम करने और परस्पर जुड़े लाभ प्रदान करने में मदद कर सकता है। वर्तमान में, इस हेतु बना फंड बहुत कम है तिसपर उपलब्ध निधियों (ऋण, कर्ज आदि) का नाम बदलकर जलवायु-फंड किया जा रहा है। विकासशील और गरीब देशों को जलवायु सुधार, विशेष रूप से स्वास्थ्य अनुकूलन के लिए, अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। जलवायु और स्वास्थ्य नीतियों में तारतम्य बनाने का समय आ गया है क्योंकि मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी की सेहत का नाता गहरे तक जुड़ा है।

(ये लेखक के विचार हैं)

गड़करी जी बधाई के पात्र तो है ही?

ओमप्रकाश मेहता

आज देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश छोटे-बड़े नेता सत्ता के झूले पर प्रसन्न मुद्रा में झूल रहे हैं, वही कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे भी है, जिन्हें मौजूदा स्थिति की काफी चिंता है। इन नेताओं में से केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गड़करी ने तो अपनी वेदना सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी कर दी, उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की फसल अब जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है, उसमें कीड़े लगने की भी चिंता बनती जा रही है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े ऐसे स्पष्टवादी नेता आज बहुत कम है, सत्तारूढ़ दल के कभी अध्यक्ष रह चुके गड़करी जी की गिनती आज भी मुखर राजनेताओं में होती है, उनकी स्पष्ट राय है कि इस फसल पर लगे कीड़ों को नष्ट करने के लिए असरकारक कीटनाशक छिड़कने की बहुत तीव्र आवश्यक्ता है, वर्ना ये कीड़ें पूरी फसल को ही नष्ट कर देगें।'' फसल बचाने के लिए यह त्वरित कदम जरूरी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी में दल बदलकर आने वाले दागी नेताओं कार्यकर्ताओं का भीषण दौर जारी है और भाजपा के वरिष्ठ नेता बिना किसी की भी विगत जाने पार्टी में सभी को प्रवेश दे रहे है। इसी व्यवस्था को इंगित करते हुए गड़करी ने यह चेतावनी पूर्ण बयान जारी किया है, उनका स्पष्ट कथन है कि जैसे-जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही है, ऐसे दौर में पार्टी को अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने अपने इस कथन को स्पष्टतः उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा कि पार्टी को कीटनाशक छिड़कने की जरूरत समझना चाहिए, क्योंकि जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती है।

बीजेपी की फसल बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी गा गई है, इसलिए अब कीटनाशक का उपयोग जरूरी हो गया है। उन्होंने नए सदस्यों के पार्टी प्रशिक्षण' पर भी जो दिया उनका कहना था कि भाजपा का मुख्य आधार चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता ही है। इसलिए इस आधार को मजबूर रखने के लिए उसे ठोस बनाकर रखना बेहद जरूरी है, उनका यह भी कहना था कि पार्टी में प्रवेशकर्ताओं की राजनीतिक विगत जानना भी बेहद जरूरी है और उनकी निष्ठा ओर सियासी चाहत को परखना भी जरूरी है। उन्हें पार्टी में प्रवेश के साथ ही पार्टी का पूरा ज्ञान कराना तथा जरूरी प्रशिक्षण पर भी गड़करी जी ने विशेष जोर दिया। अब भाजपा के वरिष्ठतम नेता नितिन गड़करी जी के ये बयान चाहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आए हो, किंतु मौजूदा राजनीतिक माहौल में इस खरी सीख का हर जगह अपना महत्व है।

देश में भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला रही है और सदस्यता की स्पर्द्धा में ऐसे लोगों को भी सदस्यता दी जा रही है, जिनकी राजनीतिक विगत परखी नही गई है, ये अवसरवादी नेता पार्टी में प्रवेश के बाद अपना कौनसा स्वरूप स्पष्ट करेगें। यह भी संदिग्ध ही है। इसी प्रक्रिया पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गड़करी जी ने चेतावनी भरी सीख जाहिर की है और प्रतीक स्वरूप कृषि कर्म की विसंगतियों का उदाहरण पेश किया है। अब पूर्व अध्यक्ष इस चेतावनी भरे बयान को पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, किंतु यहां यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों में अब ऐसी आत्मघाती चेतावनी देने वाले नेता रहे ही कितने गए है? और आज के स्पर्द्धात्मक राजनीतिक दौर में ऐसी चेतावनियों को कितने लोग गंभीरता से स्वीकार करते है। अब वरिष्ठ नेता की इस चेतावनी को कोई किसी भी रूप में ले, किंतु आज के माहौल में ऐसी चेतावनी के लिए गड़करी जी बधाई के पात्र तो है ही?

(ये लेखक के विचार हैं)

श्रीकंचनपथ

भिलाई–दुर्ग

ITR फाईल बनवाएं मात्र 499/-

- TDS रिफंड
- GST रजिस्ट्रेशन
- इनकम TAX फाइल
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- MSME रजिस्ट्रेशन
- GST रिटर्न फाइल
- CMA DATE
- फूड लाइसेंस
- BALANCE SHEET

हमारे TAX EXPERT आपकी मदद हेतु तैयार हैं

संपर्क : शेखर गुप्ता, मो. 93007-55544, 8878655544
D-6 सेक्टर-2, गुरुद्वारा के सामने देवेन्द्र नगर रायपुर

खास खबर

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितिकी बैठक 21 नवम्बर को

दुर्ग। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में 21 नवम्बर को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे आयोजित की गई है। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति वृंद अधिक फसल, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास-शहरी), स्वच्छ भारत मिशन शहरी, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यकम, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 1.0, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2.0, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-प्र.मं.पोषण (मध्यान्ह भोजन योजना), समग्र शिक्षा, डिजीटल इंडिया-सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यकम- प्रत्येक ग्राम पंचायत सामान्य सेवा केन्द्र प्रदान करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, ई-श्रम पोर्टल इत्यादि बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी।

बीएसपी टाउनशिप में पांच दिन तक बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए रोजाना बंद रहेगी 3:30 घंटे बिजली

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के अन्तर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वार्षिक रखरखाव योजना 2024-2025 के तहत टाउनषिप में विद्युतीय मेंटेनेंस एवं अनुरक्षण कार्य संपादित किये जा रहे हैं। ब्रेकडाउन को कम करने और सिस्टम की दक्षता बढ़ाने के लिए विद्युत सिस्टम के यथोचित रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नवम्बर 2024 से मार्च 2025 के दौरान एचटी सिस्टम के निवारक रखरखाव के लिए टाउनषिप के विभिन्न स्थानों में योजनाबद्ध शटडाउन किया जाएगा। इस वार्षिक रखरखाव योजना के अंतर्गत सबस्टेशन, टैपिंग, डीपी और मेंटेनेंस, ओवरहालिंग, ओवर हेड लाइनों का मेंटेनेंस, जम्पर कसना, क्षतिग्रस्त पिन को बदलना, डिस्क इंसुलेटर और लाइटनिंग अरेस्टर, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस आदि कार्य किये जायेंगे। यह कार्य प्रतिदिन योजनानुसार पूर्ण किये जाते हैं। इस कार्य के तहत टाउनषिप में 19 नवम्बर 2024 से 23 नवम्बर 2024 के मध्य विभिन्न स्थानों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेंगी। तिथि अनुसार प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं:- 19 नवम्बर 2024 को रूआबांधा व रिसाली सेक्टर, 20 नवम्बर 2024 को डायरेक्टर बंगला व सेक्टर-9, 21 नवम्बर 2024 को सेक्टर-06 का एक तिहाई हिस्सा, 22 नवम्बर 2024 को सेक्टर-01 तथा 23 नवम्बर 2024 को सेक्टर-06 का एक तिहाई हिस्सा तथा बीएमडीसी के कुछ क्षेत्र। उपरोक्त क्षेत्रों में उल्लेखित दिनांकों को प्रातः 10.00 बजे से 1.30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

विधायक चन्द्राकर ने आस्था ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन में किया गया भव्य स्वागत, राऊत नाचा और धुन पर स्टेशन हुआ राम मय

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) अंतर्गत अयोध्या के भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आज आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से रवाना किया गया। श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया।

छत्तीसगढ़ की पारम्परिक राऊत नाचा और स्थानीय वाद्यंत्र की धुन में स्टेशन में जय श्रीराम के नारे गूंज रहे थे। रेलवे स्टेशन राम मय नजर आया। रेलवे स्टेशन में राम भक्तों को तिलक, माला पहनाकर स्वागत किया गया। दुर्ग रेल्वे स्टेशन से दोपहर 12 बजे दुर्ग

ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी एवं रेलवे अधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को रवाना किया। यात्रा में दुर्ग एवं बस्तर संभाग के कुल 850 श्रद्धालुगण शामिल है।

21 नवम्बर की मध्य रात्रि दुर्ग रेल्वे स्टेशन वापसी होगी। श्रद्धालुओं ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार के अभिनव पहल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ बी.के. दुबे, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, उपसंचालक समाज कल्याण विभाग अमित सिंह परिहार एवं अन्य अधिकारी तथा जिला एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रति वर्ष 14 नवम्बर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के सम्मान के लिए दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी अनुक्रम में विगत 14 नवम्बर 2024 को जिला एवं परियोजना स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद सभागार में किया गया जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद दुर्ग विजय बघेल एवं विशिष्ट अतिथि विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव, जिला पंचायत सदस्य योगिता चन्द्राकर, लक्ष्मी साहू, एवं मिनीमाता सम्मान 2024 पुरूस्कार प्राप्तकर्ता पार्वती ढीढी, बहादुर कलारिन सम्मान प्राप्तकर्ता चित्ररेखा सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा, परियोजना अधिकारी दुर्ग (ग्रामीण) उषा झा, परियोजना अधिकारी दुर्ग (शहरी) अनिता सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला दुर्ग के पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका व समूह के सदस्य उपस्थित रही।

कार्यक्रम में जिला दुर्ग अंतर्गत 8 परियोजनाओं के 16 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पोषण माह एवं महतारी वंदन योजना व विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ अन्य विभागों से समन्वय, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, आयुष्मान कार्ड बनाना एवं जनगणना, जन्म-मृत्यु आदि कार्यों में उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सहायिकाओं को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ चिकित्सा विभाग एन.आर.सी. में भर्ती आदि कार्यों में विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय पुरूस्कार प्राप्तकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुर्ग शहरी से सुलोचना ठाकुर, दमयंत्री साहू, दुर्ग (ग्रामीण) से रत्नी ठाकुर, महेश्वरी सोनवानी, भिलाई 01 से मुनेश्वरी देवी, संगीता लहरे, भिलाई 02 से प्रेमीन देवांगन, जया गोस्वामी, अहिवारा से दीपिका बारले, उत्तरा खैरवार, धमधा से सरस्वती यादव, शारदा देवांगन, पाटन से तलिता डहरे, कामनी वर्मा, जामगांव से महेश्वरी ठाकुर, दुलारी साहू, तथा परियोजना स्तरीय सम्मान दुर्ग ग्रामीण से प्राप्तकर्ता मानकुंवर ठाकुर, बिन्दा धनकर, राधा सारथी, गंगोत्री यादव, माद्री ठाकुर, गीता महार, ललिता राजपूत, गीता साहू, वंदना बंजारे, शकुन साहू, लता त्रिपाठी, हेमलता, प्रभा देवांगन, हेमलता साहू, रेवती गौतम, उमा देवांगन, अल्का यादव, रेणु साहू तथा दुर्ग शहरी परियोजना से कविता भोंडेकर, लेखा डोंगरे, धनेश्वरी राजपूत, संगीता थापा, रश्मि साहू, सरस्वती सेन, सुरूज बाई कौशिक, माधुरी दत्ता, महेश्वरी देवांगन, सरस्वती कोसरिया, भारती यादव, हेमलता राजपूत, गायत्री साहू, सविता यादव, सुशीला निषाद, उषा चर्तुवेदी, मधू साहू, रोमा साहू को सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका गर्भवती, शिशुवती एवं जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं अनौपचारिक शिक्षा देने में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे है। समाज के इन हितग्राहियों को अपनी सेवा निरंतर अर्पित कर रही है। विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चन्द्राकर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की मातृ शक्ति को बढ़ाओं देने के लिए आयोजित महतारी वंदन योजना का शत-प्रतिशत् सफल क्रियान्वन करने की सराहना की।

एनीमिया जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग के रेडक्रॉस के तत्वाधान से एनीमिया जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा कॉलेज भ्रमण के दौरान छात्राओं की रक्त अल्पतता को लेकर चिन्ता व्यक्त की गई थी।

उनके दिशा निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में जिला चिकित्सालय दुर्ग के विषय विशेषज्ञ डॉ. रश्मि भोंसले द्वारा छात्राओं में बढ़ती रक्त अल्पतता एवं सुश्री गीतिका पवार ने सिकेल सेल एनीमिया का विश्लेषण कर इसके निदान एवं बचाव के तरीकों पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. डी.सी. अग्रवाल ने जिला प्रशासन को साधुवाद दिया कि छात्राओं की सेहत के प्रति शासन संवेदनशील है। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसायटी की प्रभारी डॉ. रेशमा लाकेश ने उन कारणों पर प्रकाश डाला जो छात्राओं में रक्त अल्पतता के लिए जिम्मेदार है। जिला प्रोजेक्ट मैनेजर यामिनी लहरे ने शासन द्वारा युवाओं के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों ने छात्राओं की रक्त अल्पतता से संबंधित शंकाओं का समाधान किया। कार्यशाला की समाप्ति पर एन.एस.एस. प्रभारी डॉ. यशेश्वरी ध्रुव ने आभार व्यक्त किया।

दस्तावेज नहीं होने पर जाति और निवास बनाने निगम बनेगा सेतु

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों का जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने निगम अनुशंसा करेगा, जिनके पास दस्तावेज का अभाव है। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता वाली परिषद ने उद्घोषणा जारी करने संबंधी विषय को सर्व सम्मति से पारित किया है।

सोमवार को हुए महापौर परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि निगम ऐसे लोगों की सूची तैयार कर उद्घोषणा जारी करेगा जो दस्तावेज के अभाव में जाति और निवास

प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे है। उद्घोषणा पत्र की औपचारिकता पूरी करने के बाद सूची को कलेक्टर, तहसील कार्यालय, सहायक आयुक्त के समक्ष प्रमाण पत्र बनाने प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अनुसुचित जाति, जन जाति को प्रमाण पत्र बनाने 1950 के पूर्व का दस्तावेज और अन्य पिछड़ा वर्ग को 1984 के पूर्व का दस्तावेज अनिवार्य है। नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कई लोग है जिनका दस्तावेज के अभाव में अब तक प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। एमआईसी बैठक में सभापति केशव बंछोर, परिषद के सदस्य जहीर अब्बास, सनीर साहू, अनिल देशमुख, चन्द्रप्रकाश सिंह निगम, संजू नेताम, परमेश्वर वैष्णव, ममता यादव, डॉ. सीमा साहू, निगम आयुक्त मोनिका वर्मा व विभाग प्रभारी उपस्थित थे।

रिसाली निगम अब टैक्स कलेक्शन करने बैंक की मदद लेगा। इसके लिए औपचारिकता पूरी की जाएगी। महापौर परिषद ने इसके लिए अनुमति भी दे दी है। राजस्व विभाग प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि करदाताओं की संपूर्ण जानकारी बैंक के माध्यम से लिए साफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इसके बाद निगम के कर्मचारी टैक्स वसूली करेगा। इस कार्य से निगम को प्रतिवर्ष 60 से 65 लाख रूपए की बचत होगी। महापौर परिषद ने निर्णय लिया है कि निगम सफाई कार्य के लिए जल्द ही निविदा निकाले। रिसाली निगम को चार हिस्सों में विभक्त कर अब निविदा का प्रकाशन किया जाएगा।

सीनियर पुरुष हैंडबाल टीम के गठन हेतु चयन स्पर्धा का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। केरल हैंडबाल संघ द्वारा 53वी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन चंदगनासेरी, जिला-कोट्टायम (केरल) में दिनांक 26 दिसम्बर से 29 दिसम्बर 2024 तक हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। उक्त सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ की 20 सदस्यीय (18 खिलाड़ी, 1 प्रशिक्षक एवं 1 प्रबंधक) सीनियर पुरुष हैंडबाल टीम भाग लेगी।

उपरोक्त संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य की सीनियर पुरुष हैंडबाल टीम के गठन हेतु चयन स्पर्धा का आयोजन आज दिनांक 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को दोपहर 2:00 बजे से हैंडबाल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, भिलाई (छ.ग.) में आयोजित किया गया। उक्त चयन स्पर्धा में विभिन्न जिलों/इकाई (महासमुन्द जिला, दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, बस्तर जिला, रायपुर जिला, जांजगीर-चांपा जिला, रायगढ़ जिला, बिलासपुर जिला एवं सी.आई.एस.एफ, बी.एस.पी., भिलाई) के 31

खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले सीनियर पुरुष हैंडबाल खिलाड़ियों का कैचिंग एंड पासिंग, पोजीशन शूटिंग, एवं खिलाड़ियों का आपस में मैच ट्रायल लिया गया। चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम निम्नानुसार है:- 1. मनीश चंद्राकर (महासमुन्द जिला), 2. विकास यादव (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 3. देवेश्वर पांडे (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 4. योगेश (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 5. मोहम्मद आमिर हुसैन (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 6. टी. रुपेश भाई (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 7. दुर्गा माझी (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 8. तौसिफ इम्तियाज (बस्तर जिला), 9. मोहम्मद आदिल अंसारी (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 10. एस. ब्रिटेन सिंह (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 11. परदीप (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 12. मिथुन कुमार (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 13. देवेन्द्र साहू (रायपुर जिला), 14. ईश्वर साहु (दुर्ग जिला), 15. वेद प्रकाश (दुर्ग जिला), 16. आदित्य चंद्राकर (महासमुन्द जिला), 17. नारायण साहु (दुर्ग जिला), 18. शेष नारायण वर्मा (दुर्ग जिला), 19. गौरव कटकवार (जांजगीर-चांपा), 20. अमन राजभर (दुर्ग जिला), 21. मोहम्मद निहाल (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 22. एम. गौतम (दुर्ग जिला), 23. के. कार्तिक कुमार (सी.आई.एस.एफ , भिलाई), 24. बासा महेश (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 25. बी. प्रवीण कुमार (सी.आई.एस.एफ भिलाई), 26. सोमेश साहू (रायगढ़ जिला), 27. कुनाल यादव (राजनांदगांव), 28. यशस्वी शर्मा (बिलासपुर जिला), 29. विवेक लोधी (बिलासपुर जिला), 30. के. हरि (दुर्ग जिला), 31. शाही रिजवान (बिलासपुर जिला), उक्त चयन स्पर्धा में छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ से चयनकर्ता के रुप में एम. सुरेश कुमार (पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक, वीर हनुमान सिंह अवार्डी एवं पूर्व साई हैंडबाल प्रशिक्षक), कुणाल (पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हैंडबाल खिलाड़ी, शहीद राजीवं पांडे पुरस्कार से सम्मानित, एन.आई.एस. प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक सी.आई.एस.एफ हैंडबाल टीम), विजय बहादुर , राजेश सरकार (पूर्व राष्ट्रीय हैंडबाल खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक, छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ) एवं समीर खान, महासचिव, छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ उपस्थित थे।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Maa Durga Electronics
9827183839
Rohit Electronics
94242-02866

Premier sales: 8959493000
A Leela Electronics: 9425507772
Reena Electronics: 9329132299
Shree Electronics: 7000827361

Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

ई-रेत संगवारी ऐपः पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को आसानी से मुफ्त रेत मिलने की राह हुई आसान

बलौदाबाजार (ए.)। बलौदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए हुए ई-रेत संगवारी मोबाईल एप्लीकेशन 1.0 के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को बड़ी सहजता एवं आसानी से रॉयल्टी फ्री रेत उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिले में अब इसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। गांव गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों द्वारा मोबाईल एप्लीकेशन का उपयोग कर अपने घर के निर्माण हेतु रॉयल्टी फ्री रेत की बुकिंग कर कार्य में तेजी आ रही है। इस ऐप के माध्यम से आसानी से ही तत्काल परमिशन जारी होते हुए 3 घंटे के भीतर ही नजदीकी अधिकृत रेत घाट से रेत उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में इस तरह पहली बार मोबाईल एप्लिकेशन के जरिए नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। बलौदा बाजार जिलें में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 26 हजार हितग्राही पंजीकृत है। श्व रेत पोर्टल से छोटे वाहन जैसे ट्रेक्टर्स से स्वीकृत खदानों में रायल्टी मुक्त निकासी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। एक आवास निर्माण में 5 ट्रेक्टर ट्रिप (15 घन मीटर) रेत की आवश्यकता होगी। एक हितग्राही अधिकतम 5 ट्रिप तक रेत का निकासी कर सकेगा।

विधायक मोतीलाल साहू ने किया डेढ़ करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-1 के तहत

यतियतनलाल वार्ड नम्बर 4 के तहत भनपुरी में पाटीदार भवन के पास चर्च के पास से लेकर विजय नगर क्षेत्र तक एवं अन्य विभिन्न स्थानों के मार्गो में लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की स्वीकृत लागत से सड़क डामरीकरण कार्य शीघ्र करवाने यतियतनलाल वार्ड नम्बर-4 की पार्षद श्रीमती टेसू नन्दकिशोर साहू सहित नगर निगम जोन-1 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव, कार्यपालन अभियंता डी. के. पैकरा, कार्यपालन अभियंता योजना अंशुल शर्मा, वार्ड के निवासी गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, आमजनों, नवयुवकों की उपस्थिति में श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर भूमिपूजन करते हुए नागरिकों को एक शानदार सौगात दी। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने भूमिपूजन कर तत्काल सड़क डामरीकरण कार्य प्रारम्भ करवाकर उसे गुणवत्ता एवं समयसीमा का विशेष ध्यान रखकर जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से शीघ्र प्राथमिकता से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बृजमोहन के प्रयासों से सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मिली मंजूरी

धरसींवा-बलौदाबाजार क्षेत्र में 2331.57 लाख की बाढ़ नियंत्रण योजना, सुंगेरा एनीकट, पड़कीडीह स्टापडैम स्वीकृत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों और अनुशंसा के फलस्वरूप राज्य सरकार ने धरसींवा और बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री साय और जल संसाधन मंत्री कश्यप को पत्र लिखकर रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा के बरतनारा बाढ़ नियंत्रण योजना, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड तिल्दा (बलौदाबाजार विधानसभा) के अंतर्गत कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट का निर्माण और विकासखण्ड सिमगा (बलौदाबाजार विधानसभा) के अंतर्गत बंजारी नाले पर पड़कीडीह स्टापडैम निर्माण कार्य की मांग की थी। जल संसाधन विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिए 2331.57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में पेयजल, भू-जल संवर्धन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं का समाधान होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार ग्राम बरतनारा के पास खारून नदी पर 630 मी. लम्बाई में तटबंध निर्माण के लिए 856.15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वहीं विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू. 904.14 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के निर्माण से क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन, आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। विकासखंड-सिमगा (तिल्दा) की बंजारी नाले पर पड़कीडीह स्टापडेम निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू. 571.28 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के निर्माण से क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन, आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

सांसद बृजमोहन ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी और कृषकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करें।

यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों के फिटनेस व दस्तावेजों की जांच

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर-गरियाबंद। शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूली बच्चों को लाने लेजाने वाहनों का फिटनेस और वाहन संबंधित दस्तावेज की जांच रविवार को पुलिस ग्राउंड में जिला परिवहन अधिकारी कोतवाली प्रभारी ओमप्रकाश यादव यातायात पुलिस से रामाधर मरकाम, धर्मेंद ठाकुर, अनिल पांडे,वीरेंद्र पटेल, संजय सूर्यवंशी भूपेंद ठाकुर की उपस्थिति जिला मुख्यालय में संचालित स्कूलों स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों के फिटनेस वाहनों के रख रखाव व अन्य वाहन संबंधित जांच किया गया।

फाइल फोटो

मिली जानकारी के अनुसार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देश व डीएसपी सुश्री निशा सिन्हा के मार्गदर्शन वाहनों के सड़क सुरक्षा के नियमों का सुनिश्चितीकरण किया जाना है इसके तहत पुलिस ग्राउंड में स्कूलों के वाहनों की फिटनेस परमिट,वाहनों के पॉल्यूशन,बीमा टेक्स तो किया गया साथ ही उन वाहनों में चलने वाले चालक परिचालक का नेत्र जांच व अन्य शारीरिक संबंधित जांच कर वाहन चालक,परिचालक को वर्दी अनिवार्य रूप से पहनने का निर्देश दिए। जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि प्राय:यह देखने में आ रहा है कि विशेषकर शहरों में मोपेड, दो पहिया वाहन,ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस आदि में ओवरलोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है।

वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लटककर विद्यार्थी आवागमन कर रहें है। इसके पीछे शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिकों चालकों, पालकों एवं स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों एवं मानदंडों का पालन नहीं किया जाना मुख्य कारण हैं। अक्सर ऐसी चुकें स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह जानलेवा भी साबित होती रही है। इस परिपेक्ष्य में स्मरण हो कि पूर्व में भी मुख्य सचिव द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने, सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन करने, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और समीक्षा नियमित रूप से करने,सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय और प्रयास तथा सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिए गए है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा- निर्देश पर राज्य में अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षाद्ध के माध्यम से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

जिलों में खासकर शहरी और नगरीय इलाकों में स्कूली विद्यार्थियों को जोखिमपूर्ण दुर्घटना से बचाने की दिशा में परिवहन, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय विकास, सहित संबंधित हितधारकों जैसे-शाला प्रबंधन समिति, पालक समिति, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा संगठनों, निजी शैक्षणिक संस्थाओं आदि के संयुक्त प्रयासों के साथ एक सुदीर्घ कार्ययोजना एवं रणनीति बनाकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसकी समयबद्ध तरीके से मानिटरिंग भी होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही भी की जाए,जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके।वही नगर के मुख्यमार्ग में खड़े अस्त व्यस्त वाहनों को सुनिश्चित करने के लिए एसपी सर के निर्देशानुसार नगर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने रोड के दोनों ओर चुना डालकर लाइनिंग किया गया।

ट्रेन में रील्स बनाने वालों की अब खैर नहीं, रेलवे ने जारी किया आदेश

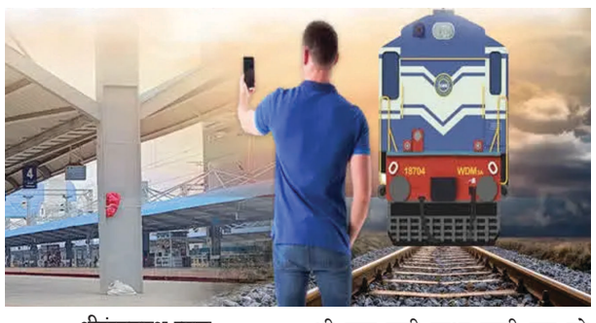

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रेलवे बोर्ड द्वारा देशभर के जोन व मंडलों के लिए जारी आदेश में साफ कहा है कि रेल पटरियों या फिर ट्रेन के भीतर रील बनाने वालों पर अब सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए जानलेवा स्टंट या फिर तरह-तरह की हरकत कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने वीडिया को पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी।

कुछ इस तरह का आदेश रेलवे बोर्ड ने अपने जोन अफसरों को जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन में बाधा खड़ी करते हैं और यात्रियों को इससे असुविधा होती है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसे सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में बाधा खड़ी करना और खतरे की श्रेणी में रखा गया है। रेलवे ट्रैक किनारे, ट्रेन के सामने, रेलवे कोच, ट्रेन के गेट के सामने के अलावा गुड्स ट्रेन के उऊपर खड़े होकर व चलती गुड्स ट्रेन में वीडिया व रील बनाने वालों पर।

रील व वीडियो बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन को लेकर भी एक बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। रेल पटरियों पर सामान रखकर भी वीडियो शूट कर रहे हैं। इससे सुरक्षित परिचालन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी ऐसे लोग खतरे में डाल रहे हैं। लिहाजा रेलवे बोर्ड ने अपने अफसरों से रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ कोई ढील न बरतने की नीति अपनाने के लिए कहा है। यदि रील बनाने वाला ट्रेन में किसी भी तरह से परेशानी पैदा करता है, तो उसे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सोशल मीडिया में यंगस्टर्स द्वारा खतरनाक स्टंट करते रील अपलोड किया गया है। इसके वायरल होने के बाद रेलवे बोर्ड ने इसे गंभीरता से लिया है। अपलोड वीडियो में युवा चलती ट्रेन के अलावा पटरियों में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो और रील अपलोड है जिसमें सेल्फी लेते वक्त युवा ट्रेन के करीब आ रहे हैं। इसके चलते हादसा भी हुआ है। इसके बाद भी इस तरह के वीडियो और रील लगातार बन रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड भी हो रहे हैं। इस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए RPF व GRP साझा अभियान चलाएगी।

गुरु घासीदास विवि व नरेंद्र मोदी अध्ययन केन्द्र के साथ शोध समझौता पर हस्ताक्षर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र (नमो केंद्र) ने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (GGV) के साथ एक शोध समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर आधिकारिक रूप से विश्वविधालय के रजिस्ट्रार और नमो केंद्र के प्रबंध ट्रस्टी प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने 7 नवंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए। शोध समझौता ज्ञापन (एमओयू) अंत:विषय अनुसंधान विकसित करने और दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। इस अकादमिक सहयोग से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों शोध के क्षेत्रों को लाभ मिलने के कार्य करेंगे, क्योंकि यह दोनों संस्थानों द्वारा छात्रों और शोधार्थियों को शैक्षणिक और बौद्धिक विकास में योगदान देना चाहता है।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने अकादमिक सहयोग के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, यह समझौता ज्ञापन अकादमिक शोध में

एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के साथ मिलकर काम करके, हमारा उद्देश्य ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और अंत:विषय अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे संस्थानों और व्यापक शैक्षणिक समुदाय दोनों को लाभ होगा। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के सभापति प्रो. जसीम मोहम्मद ने भी इस शैक्षणिक सहयोग पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, हमें एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के साथ सहयोग करने पर गर्व है। यह समझौता ज्ञापन हमें अनुसंधान, शैक्षणिक विकास के लिए नए रास्ते तलाशने और वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य में सार्थक योगदान देने की अनुमति देगा। हम शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार के अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।

हालांकि, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल और भारत भर के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय संस्थानों के साथ शोध समझौता ज्ञापन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने इस सहयोग के लिए अपने शिक्षा विभाग में प्रोफेसर संबित कुमार पाधी को विश्वविद्यालय में केंद्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो दोनों संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यान्वयन और समन्वय की देखरेख करेंगे। सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज (नमो केंद्र) एक वैश्विक शोध केंद्र है जो अंत:विषय अध्ययनों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विषयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग विकसित करने के लिए समर्पित है, जबकि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह समझौता ज्ञापन अकादमिक सहयोग में एक आशाजनक नया अध्याय जोड़ता है, जो दोनों संस्थानों को शोध, नवाचार और बौद्धिक विकास के लिए नए रास्ते तलाशने के अवसर प्रदान करता है।

अतिक्रमण की सूक्ष्म जांच कर धारा 36 और 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई के दिये निर्देश

संभागायुक्त ने पलटा कलेक्टर व एसडीएम का आदेश

धमतरी जिले की कुर्रा ग्राम पंचायत का मामला, एक माह में निराकरण के आदेश भी दिए

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलट ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच के विरुद्ध अतिक्रमण की शिकायत की सूक्ष्म जाँच कर विधि अनुरूप निराकरण करने के निर्देश जारी किए है। श्री कावरे ने इस प्रकरण में कलेक्टर और एसडीएम के फैसले में प्रस्तुत साक्ष्यों का पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 प्रावधानों के तहत सूक्ष्म जाँच कर एक माह में निराकरण के आदेश जारी किए है।

धमतरी जिले की कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिजनों द्वारा चार स्थानों पर गाँव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण,अतिक्रमित ज़मीन पर पक्का मकान और दुकान बनाकर लाभ लेने की शिकायत उप सरपंच और पंचों ने की थी। शिकायत की जाँच भखारा के तहसीलदार ने की और सरपंच के परिजनों पर अर्थदंड लगाया था। शिकायतकर्ताओं ने इस पर आगे कार्रवाई के लिए कुरुद के एसडीएम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया परंतु एसडीएम ने प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया था। एसडीएम के फैसले के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की थी। धमतरी कलेक्टर ने भी एसडीएम के फैसले को सही मानते हुए प्रकरण में अपील की माँग ख़ारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और एसडीएम के फैसले के विरुद्ध रायपुर संभागायुक्त न्यायालय में अपील की थी।

कमिश्नर श्री कावरे ने पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जिरह के लिए बुलाया और प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्री कावरे ने एसडीएम के आदेश और कलेक्टर के अपील खारिज करने के फैसले को पलट दिया। संभागायुक्त ने प्रकरण की सुनवाई के बाद उसे पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई योग्य माना। उन्होंने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों, अवैध अतिक्रमण पर भखारा तहसीलदार के प्रतिवेदन, सरपंच पर शासकीय विकास कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता सहित सरपंच के परिजनों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की भी सूक्ष्म जाँच करने के निर्देश दिये है । कमिश्नर ने कुरुद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह जाँच एक माह में पूरी कर विधिसम्मत निर्णय देने के भी आदेश दिए है।

आरना इंटरप्राईजेस
कांटावाला
वाटर प्यूरी फायर के विक्रेता एवं सुधारक
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
इलेक्ट्रानिक तराजू एवं सीसीटीवी कैमरा के विक्रेता व सुधारक
सर्कुलर मार्केट केम्प-2, भिलाई, न्यू जेपी स्पोर्ट्स के सामने
7828844440, 9993045122
नया बस स्टैण्ड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 09981370285, 9302833333

आर्टिफिशियल ज्वैलरी के विक्रेता
अनुप ट्रेडर्स
सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

प्रमोद इंटरप्राइजेस
गेंहू, चांवल एवं दाल के थोक विक्रेता
लिंग रोड, केम्प-2, भिलाई-दुर्ग
फोनः 0788-2225449, 93290-13017

जीन्स
टी-शर्ट
शर्ट
ट्राउजर
भारत जींस
जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई

BIHAR
BOOT HOUSE
Jawahar Market, Power House
Bhilai 9826181183

पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है केल, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजन

केल एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, जिसे आमतौर पर सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केल से कई स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? यहां हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और लाजवाब केल से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने में भिन्नता भी ला सकते हैं।

केल के पकोड़े

केल के पकोड़े एक बेहतरीन स्नैक है, जो चाय के साथ अच्छे लगते हैं।इसे बनाने के लिए सबसे पहले केल की पत्तियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कटे हुए केल डालें और अच्छी तरह मिलाएं।अब गर्म तेल में इस मिश्रण को छोटे-छोटे भागों में डालकर सुनहरा होने तक तलें, फिर गर्मागर्म पकोड़े हरी चटनी के साथ परोसें।

केल का परांठा

केल का परांठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय खा सकते हैं।इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक कटी हुई केल की पत्तियां, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर आटा गूंध लें।अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें, फिर गर्मागर्म परांठे को दही या अचार के साथ परोसें।

केल की सब्जी

केल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लेहसुन का पेस्ट भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाला तैयार करें।अब इसमें बारीक कटी हुई केल की पत्तियां डालें और थोड़ी देर पकने दें।इसके बाद इसमें पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि केल नरम न हो जाएं, फिर इसमें गरम मसाला मिलाकर इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

केल का रायता

अगर आप कुछ ठंडा और ताजगी भरा खाना चाहते हैं तो केल का रायता ट्राई कर सकते हैं।इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई केल की पतियां, भुना हुआ जीरा, नमक और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें।आपका केल का रायता तैयार है। इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है।

केल की खिचड़ी

खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी केल की खिचड़ी ट्राई की?इसे बनाने के लिए मूंग दाल और चावल को धो लें।अब कुकर में घी, जीरा, हींग और हल्दी डालें, फिर इसमें मूंग दाल और चावल डालकर पानी और नमक मिलाएं। कुकर बंद करें।ठंडा होने पर इसमें बारीक कटी हुई केल की पत्तियां डालें। आपकी केले की खिचड़ी तैयार है।

सनी लियोन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म मंदिरा 22 नवंबर को रिलीज होगी

कनाडाई अभिनेत्री सनी लियोन अपनी आगामी हॉरर-कॉमेडी फिल्म मंदिरा के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस फिल्म का निर्देशन आर युवान ने किया है और इसे कोमलपति श्रीधर ने प्रस्तुत किया है। 22 नवंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म अपने प्रभावशाली पोस्टर, झलकियों, टीजर, ट्रेलर और गानों के साथ चर्चा बटोर रही है। सनी लियोन मंदिरा की मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो एक राजकुमारी है जो एक आत्मा के रूप में वापस जीवन में आती है।

ट्रेलर को 2 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जिसमें सनी को पहले कभी न देखे गए किरदार में दिखाया गया है, जिसमें वह एक्शन सीक्वेंस करती नज़र आ रही हैं और अपनी कॉमेडी टाइमिंग का प्रदर्शन कर रही हैं। फ़िल्म में मशहूर कॉमेडियन योगीबाबू, सतीश और योगी बाबू भी हैं, जो फ़िल्म में हास्य का तड़का लगाते हैं। विज़न मूवी मेकर्स के तहत साई सुधाकर कोमलपति द्वारा निर्मित, मंदिरा हॉरर और कॉमेडी तत्वों के एक विशिष्ट मिश्रण का वादा करती है।

जिस्म 2, रईस और कोटेशन गैंग पार्ट 1 जैसी फिल्मों के लिए मशहूर सनी लियोनी का भारत में एक खास प्रशंसक वर्ग है। तेलुगु में उन्होंने करंट थिगा और पीएसवी गरुड़ वेगा जैसी फिल्मों से दर्शकों को प्रभावित किया है। मंदिरा के साथ, उनसे एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। फिल्म की रिलीज के आसपास चर्चा पैदा करने के लिए निर्माता हैदराबाद में सनी लियोनी को लेकर एक बड़े प्रचार कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। मंदिरा की रिलीज के लिए तैयारियां चल रही हैं, वहीं सनी लियोनी के प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेलेन, रंगीला, वीरमादेवी, हेडलाइंस टुडे, यूआई, शेरो और द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसी फिल्मों की लाइनअप के साथ, सनी लियोनी भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखने के लिए तैयार हैं।

तृप्ति डिमरी ने रेड आउटफिट में गिराई बिजली, एक्ट्रेस ने फैंस को बनाया दीवाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वह रेड आउटफिट में कहर ढाती नजर आ रही हैं। तृप्ति ने इस लुक में एक रेड लेदर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जो उनकी स्टाइल को और भी ग्लैमरस बना रही है। लाइट मेकअप, खुले बाल और स्टाइलिश ईयररिंग्स के साथ तृप्ति ने कई कातिलाना पोज़ दिए हैं, जो फैंस को दीवाना बना रहे हैं। तृप्ति के इस हॉट लुक को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। उनके फॉलोअर्स कमेंट्स में दिल और फायर इमोजी के साथ उनकी तारीफ कर रहे हैं।

तृप्ति का ये लुक और उनकी कातिल अदाएं फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं। इस ड्रेस में तृप्ति का कॉन्फिडेंस और उनकी अदा वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। उनके स्टाइल और पर्सनालिटी के इस अनोखे मेल ने फैंस को एक बार फिर से उनका दीवाना बना दिया है।

हाल ही में, त्रिप्ति ने स्लीवलेस मिनी ड्रेस में भी सबका ध्यान खींचा, जिसे सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट लक्ष्मी लेहर द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में दिखाया गया था। इस शानदार ड्रेस में डीप प्लंजिंग नेकलाइन, प्लीटेड डिटेलिंग और बैकलेस डिज़ाइन था, जो उनके आकर्षक लुक को और भी निखार रहा था। उन्होंने इस आउटफिट को व्हाइट टेक्सचर्ड हाई हील्स और स्टेटमेंट रिंग के साथ पूरा किया।

अपने बेहतरीन फैशन सेंस के साथ, त्रिप्ति डिमरी लगातार ट्रेंड सेट करती रहती हैं और प्रशंसकों को प्रेरित करती रहती हैं। उनकी बोल्ड रेड लेटेक्स ड्रेस और शानदार मिनी ड्रेस लुक्स ने उन्हें स्टाइल आइकन के रूप में स्थापित किया है।

हनुमान बनेंगे प्रभास?, केजीएफ के मेकर्स ने जारी किया शॉकिंग पोस्टर

ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने हाल ही में एक सरप्राइजिंग पोस्टर शेयर किया है। जिसे देखते ही फैंस एक्साइटेड भी हैं और कंफ्यूज भी कि ये पोस्टर किस प्रोजक्ट का है। दरअसल हाल ही में होम्बले फिल्म्स ने प्रभास के साथ तीन मेगा प्रोजेक्ट का एलान किया था ये उनमें एक का अनाउंसमेंट हो सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट हालांक इसका आज 16 नवंबर को हो जाएगा। आइए जानते हैं पोस्टर में क्या है।

होम्बले फिल्म्स ने जो पोस्टर रिलीज किया है उसमें सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा है जो किसी माइथोलॉजिकल फिल्म का लग रहा है। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, जब आस्था को चुनौती दी जाती है, तो वह प्रकट होता है। पहली झलक आज 16 नवंबर को दोपहर 3:33 बजे। हालांकि यह अनाउंसमेंट ऑफिशियल है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि ये पोस्टर किस फिल्म और किस एक्टर का है। इसका पता कल यानि 16 नवंबर को शाम 3.33 बजे ही चलेगा।

हाल ही में सालार और केजीएफ के मेकर्स होम्बले फिल्म्स ने 8 नवंबर को प्रभास के फैंस को बड़ी गुडन्यूज दी। होम्बले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था- रेबल स्टार प्रभास के साथ जुड़कर बहुत हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हम प्रभास के साथ इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल तक पहचान दिलाने के लिए तीन फिल्मों का एलान करते हैं, प्रभास के साथ फिल्म का यह हमारा कमिटमेंट नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा, जो कभी ना भुला पाने वाला होगा, स्टेज सज चुकी है और अब रास्ते की कोई सीमा नहीं है, तैयार रहें, सालार 2 के साथ हमारा यह सफर शुरू होता है। अब होम्बले फिल्म्स ने इस अनाउंसमेंट के साथ फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। इसीलिए फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि हो ना हो ये फिल्म प्रभास की ही है।

तीन साल तक के लिए हुए बुक

बता दें प्रभास की तीनों फिल्में साल 2026, 2027, 2028 तक रिलीज होंगी। यानि प्रभास अब तीन साल तक होम्बले फिल्म्स के लिए बुक हो गए हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद से प्रभास के फैंस काफी खुश और एक्साइटेड हो गए और अब इस नए अनाउंसमेंट के बाद से फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें, प्रभास बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में हैं। प्रभास के फैंस को इस फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार है।

क्रॉप टॉप पहन भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने शेयर की बेहद हॉट फोटोज

भोजपुरी क्वीन मोनालिसा आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। उनका बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स इंस्टाग्राम पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपनी बेहद ही हॉट फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज में उनका स्टनिंग अंदाज देखकर फैस एक बार फिर से मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

मोनालिसा अपनी बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर अक्सर फैंस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट स्टनिंग लुक्स की फोटोज फैंस के बीच शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनका कातिलाना अंदाज देखकर फैंस बेकाबू हो गए हैं।

मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान स्लीवलेस क्रॉप टॉप और डेनिम जींस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी गॉर्जियस नजर आ रही थीं। ओपन हेयर और नो मेकअप लुक कर के एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने आउटलुक को कंप्लीट किया है।

इन फोटोज में आप देख सकते हैं मोनालिसा कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक किलर अंदाज में पोज देती हुई अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस की इन फोटोज पर कई यूजर्स ने कॉमेंट्स करते हुए अपने रिएक्शंस दिए हैं। एक यूजर ने लिखा है- सो ब्यूटिफुल। दूसरे यूजर ने लिखा है स्टनिंग।

खाली पेट फल खाने के फायदे हैं या नुकसान?

खाली पेट फल खाने को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे शरीर को पोषण मिलता है, जबकि कुछ लोग इसे हानिकारक मानते हैं। इस लेख में हम इन धारणाओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि खाली पेट फल खाना सही है या नहीं। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। इसके अलावा, हम यह भी जानेंगे कि कब खाली पेट फल खाना फायदेमंद होता है।

खाली पेट फल खाने से पाचन बेहतर होता है?

कई लोग मानते हैं कि खाली पेट फल खाने से पाचन स्वास्थ्य बेहतर होता है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी तरह सही नहीं है। फलों में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें खाली पेट खाया जाए। अगर आप पहले से ही किसी गैस्ट्रिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो खाली पेट फल खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।

क्या सुबह-सुबह केवल फल खाना वजन घटाने में मदद करता है?

वजन घटाने के लिए कई लोग सुबह-सुबह खाली पेट फल खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फलों में कैलोरी कम होती है और ये विटामिन और मिनरल का अच्छा स्रोत होते हैं। हालांकि, केवल फलों पर निर्भर रहना संतुलित डाइट नहीं मानी जा सकती। वजन घटाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का संतुलन भी जरूरी होता है, ताकि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें और ऊर्जा बनी रहे।

क्या खाली पेट खट्टे फल खाना सुरक्षित है?

नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों को लेकर धारणा बनी हुई है कि इन्हें खाली पेट खाने से एसिडिटी बढ़ सकती है।हालांकि, यह सभी लोगों पर लागू नहीं होता। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आप इन्हें बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। वहीं, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उन्हें इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ सकती है।अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खाली पेट खट्टे फल खाएं।

क्या रात को सोने से पहले फल खाना सही होता है?

रात को सोने से पहले हल्का भोजन करना अच्छा माना जाता है, ताकि नींद अच्छी आए और पाचन भी ठीक रहे। ऐसे में कुछ लोग रात को सोने से पहले सिर्फ फल खाते हैं, जो एक स्वस्थ विकल्प हो सकता है। ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज लेने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए फलों का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। इससे नींद भी अच्छी आएगी और पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा।

24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 दिसंबर तक

वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए स्वागत समिति का हुआ गठन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा राजधानी रायपुर में 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह पांच दिवसीय प्रतियोगिता 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। जिसमें तीरंदाजी एवं फुटबॉल के लगभग 800 प्रतिभागी भाग लेंगे। शबरी आश्रम परिसर रायपुर में आयोजित बैठक में प्रतियोगिता के तैयारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्वागत समिति का गठन किया गया।

वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के प्रांतीय सचिव अनुराग जैन ने इस कार्यक्रम के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी, तत्पश्चात स्वागत समिति का गठन किया गया जिसमें सभी क्षेत्र (चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, समाज) के सेवाभावी, गणमान्य व्यक्तियों के नाम सामने आए जिनमें से वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूणत विधायक, पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, एनआईटी रायपुर के संचालक प्रो.रमन्ना राव, आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद शुक्ल, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी समाजसेवी वसंत अग्रवाल, व्यवसायी सरल मोदी, राम मंदिर ट्रस्ट के ब्रज लाल गोयल, पार्षद अमर बंसल, डॉ आनंद जोशी, आदि के नाम प्रमुख हैं। सर्वसम्मति से केदार कश्यप को इस समिति का अध्यक्ष और अमर बंसल को सचिव बनाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कौशल्या विष्णु देव साय और शबरी कन्या आश्रम की बहनों द्वारा संध्या आरती के साथ हुई। कौशल्या विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि चूकी इस प्रतियोगिता के लिए पूरे भारतवर्ष से जनजाति क्षेत्र के प्रतिभागी भाग लेंगे अत: हम सबका एक कर्तव्य और दायित्व है कि उनके लिए यह प्रतियोगिता यादगार साबित हो, इसका प्रयास करना चाहिए। समिति के अध्यक्ष वन मंत्री केदार कश्यप ने भी आश्वस्त किया कि हम सबके सहयोग से यह प्रतियोगिता सभी के लिए यादगार होगी।

इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री भगवान सहाय ने कल्याण आश्रम द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर वनवासी समिति के बालक और बालिकाओं का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि लगभग दो लाख छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष प्रारंभिक स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिताओं में जनजाति क्षेत्र से भाग लेते हैं। वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के प्रांतीय सचिव अनुराग जैन ने बताया कि जनजाति समाज के विकास के लिए 1952 में जशपुर से शुरू हुई यह यात्रा निरंतर जारी है और पूरे देश में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिनमें जनजाति समाज के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के लाखों बालक एवं बालिकाएं जिन्हें वह सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती जिसके अभाव में वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वनवासी विकास समिति काम करती है।

सरकार व जनता के बीच विश्वास का एक सेतु है भारतीय लेखा परीक्षा विभाग-रमेन डेका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक सेतु है, जो सुनिश्चित करता है कि हर संसाधन का सदुपयोग हो और हर निर्णय समाज के हित में हो। राज्यपाल रमेन डेका ने आज प्रधान महालेखाकार कार्यालय में लेखा परीक्षा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर 22 नवम्बर 2024 एक सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा।

महालेखाकार कार्यालय के आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि लेखा परीक्षा केवल सरकारी व्यय और राजस्व की जांच तक सीमित नहीं है; यह प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, और जनसेवा में उत्तरदायित्व का एक सशक्त माध्यम है। भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में इस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह न केवल सरकारी कार्यों में वित्तीय अनुशासन लाने का कार्य करता है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाता है। इस विभाग के अधिकारियों की निष्पक्षता और कर्मठता ने इसे एक सशक्त संस्थान के रूप में स्थापित किया है। श्री डेका ने कहा कि भारतीय प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में नियंत्रक और महालेखाकार (सीएजी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान निर्माताओं ने कैग को वित्तीय नियंत्रण में स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया है जिससे इसे लोक वित्त की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख दर्जा प्राप्त है।

भारतीय प्रशासनिक ढांचे में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण में कैग की भूमिका की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कैग के निरीक्षण से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की समुचित निगरानी और पारदर्शिता बनी रहती है जिससे लोक कल्याण को लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है।

राज्यपाल ने तेजी से बढ़ते हुए तकनीकी युग में लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में भी नवाचार की आवश्यकता बताते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत बढ़ती ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण के चलते लेखा परीक्षकों को आधुनिक उपकरणों और तकनीकी दक्षताओं से लैस होना जरूरी है। इससे न केवल काम की गति तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की परंपराओं को बनाए रखते हुए निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उनकी मेहनत और ईमानदारी से ही जनता का भरोसा और मजबूत होगा।

युवाओं में बढ़ता विश्वास बस्तर ओलंपिक बना खास

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आयोजित बस्तर ओलम्पिक की स्पर्धाओं में बीजापुर के सुदूर क्षेत्रों के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के तहत ब्लॉक स्तरीय स्पर्धा का शुभारंभ आज बीजापुर और भैरमगढ़ ब्लाक हुआ। अंदरूनी क्षेत्रों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर सुशासन के सूर्योदय के साक्षी बने हैं।

बीजापुर के मिनी स्टैडियम एवं भैरमगढ़ में ब्लॉक स्तरीय स्पर्धाएं आज 18 से शुरू हुई है, जो 21 नवंबर तक चलेंगी। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस्तर ओलंपिक में 14-17 वर्ष एवं 17 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी गोला फेक, तवा फेक, लंबी कूद, लंबी दौड़, रिलेरेस, बैडमिंटन, फुटबाल, कबड्डी, तीरंदाजी, कराटे, वॉलीबाल, रस्साकसी में हिस्सा ले रहे हैं।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बी पुष्पा राव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीना रावतिया नगरपालिका अध्यक्ष बेनहुर एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ आज बीजापुर के मिनी स्टेडियम में हुआ।

अतिथिगणों ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल भावना से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं जिला खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल, एसडीएम बीजापुर उत्तम सिंह पंचारी, सीईओ जनपद पंचायत गीत कुमार सिंहा सहित अधिकारी-कर्मचारी, खेल प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

महिला आयोग की नई सदस्यों को संभागों का दायित्व

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य संभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी। महिला आयोग की बैठक में नये सदस्यों की नियुक्ति होने के पश्चात् संभागवार न्यायपीठ का गठन किया गया।

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी सदस्यों को स्वयं से संभाग चयन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आगामी 19, 20 और 21 नवंबर 2024 को रायपुर मुख्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित सुनवाई रखी गई है, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे सम्मिलन बैठक का आयोजन किया गया है।

नए सदस्यों को संभागवार दायित्व इस प्रकार है। बस्तर संभाग का प्रमुख प्रभार सुश्री दीपिका सोरी एवं अतिरिक्त प्रभार ओजस्वी मंडावी, सरगुजा सभाग का प्रमुख प्रभार प्रियंवदा सिंह जुदेव एवं अतिरिक्त प्रभार सरला कोसरिया, बिलासपुर संभाग का प्रमुख प्रभार सरला कोसरिया एवं अतिरिक्त प्रभार प्रियंवदा सिंह जुदेव संभालेंगी है। इसी प्रकार रायपुर संभाग का प्रमुख प्रभार लक्ष्मी वर्मा एवं अतिरिक्त प्रभार सुश्री दीपिका सोरी व दुर्ग संभाग का प्रमुख प्रभार ओजस्वी मंडावी एवं अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मी वर्मा संभालेंगी। बैठक में आयोग के समस्त सदस्य सहित आयोग सचिव मनोज कुमार सिन्हा, सहायक संचालक पुष्पा किरण कुजूर एवं समस्त कर्मचारीगण उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का हुआ शुभारंभ

सुकमा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र परिसर सुकमा में जिला स्तरीय आयोजित कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ विधायक चौतराम अटामी ने रिबन काटकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी, नगर पालिका के अधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। चौतराम अटामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के जीवन में सुधार लाने वाली क्रांतिकारी पहल है। योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को सशक्त बनाती है।

जल जीवन मिशन से अब गांव के घर तक मिल रहा शुद्ध पेयजल

जिले में 1 लाख 47 हजार से अधिक कार्य पूर्ण

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन योजना के तहत् लोगों को हर घर तक शुद्ध पेजय जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत् जशपुर जिले में 1 लाख 99 हजार 930 कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 1 लाख 47 हजार 500 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इनमें से 62 हजार 930 में शुद्ध पेयजल की सुविधा सतत् रूप से दी जा रही है। इनमें मुख्यालय से 25 कि.मी. दूरी पर स्थित जंगल के किनारे बसा ग्राम बोड़ोकच्छार ग्राम शामिल हैं।

जहां में 96 क्रियाशील घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से घर-घर तक शुद्ध पेय जल पहूंचाया जा रहा है। घर पर पानी आने से सभी ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है।

जल जीवन मिशन के आने से पूर्व ग्रामीण अपनी पानी की दैनिक आवश्यकताओं के लिए हैण्डपम्प एवं कुओं पर निर्भर रहते थे, मुख्यत: महिलायें पानी भरने के कार्यों को करती थी जिसमें दिनों का काफी समय लग जाया करता था एवं मौसमों की वजह से गर्मियों में जल स्तर का नीचे जाने से नलकूप में पानी देर से आना अथवा नहीं आने की समस्या एवं बारिसों के पानी से तबीयत ज्यादा खराब होने की समस्याएं रहती थी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एस.बी.सी ने बताया कि बोड़ोकच्छार में योजना के अंतर्गत 2 एकल ग्राम नल जल योजनाएं लगी है जिसमें एक 12 मी. उंचाई की सोलर योजना लगी है। जिसकी क्षमता 10000 ली. की है। जिससे 32 परिवारों को पीने का पानी पर्याप्त हो जाता है और दूसरी बिजली संचालित योजना है। जिससे 60 परिवारों को पानी पहुंचाया जा रहा है। जिसमें 12 मी. उंचाई की 10000 ली. क्षमता की टंकीयां लगाई गई है। जल जीवन मिशन के आने के बाद अब गांव के हर घर में नल से पानी आ रहा है जिससे अब पानी भरने नहीं जाना पड़ता एवं दिन का काफी समय बचता है योजना के आने से अब पानी जांच कर उपयोग में ला रहे हैं जिससे जल जनित बीमारियाँ बाकी सालों के मुकाबले काफी कम हो गई है। आज की स्थिती में योजना के ग्राम आये एवं चालू हुए डेढ़ साल से उपर हो गया है सभी ग्रामीण काफी खुश है वे टंकी की सफाई भी करते हैं, गांव में पानी की समस्या पूर्ण खत्म हो गई है।

भारत की सूक्ष्मजीवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए 'वन डे वन जीनोम' पहल

नई दिल्ली(पीआईबी)। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (ब्रिक) ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवीय क्षमता को दर्शाने के लिए 'वन डे वन जीनोम' पहल की शुरुआत की है। भारत के जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्यए कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई) में आयोजित ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर 'वन डे वन जीनोम पहल' की शुरुआत की घोषणा की थी।

'वन डे वन जीनोम' पहल हमारे देश में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग-अलग प्रजातियों को उजागर करेगी और पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाएगी। सूक्ष्मजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सभी प्रकार के जैव-रासायनिक चक्रों, मिट्टी के निर्माण, खनिज शोधन, जैविक कचरे के अपघटन और मीथेन उत्पादन के साथ-साथ विषाक्त प्रदूषकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचयी रूप से वे हमारी पृथ्वी पर समान स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं। कृषि में, वे पोषक चक्रण, नाइट्रोजन के निर्धारण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीट और खरपतवारों तथा अवांछनीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सूक्ष्मजीव पौधों के साथ सहजीवी रूप से जुड़ते हैं और उन्हें पोषक तत्व और पानी के अवशोषण में मदद करते हैं। वे मानव शरीर का अपरिहार्य अंग हैं। मानव शरीर में मानव कोशिकाओं की संख्या की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्मजीव कोशिकाएं होती हैं। वे हमारे पाचन, प्रतिरक्षा और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। सभी संक्रामक रोग मुख्य रूप से रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं, दूसरी ओर गैर-रोगजनक सूक्ष्मजीव संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं।

जीनोम अनुक्रमण से सूक्ष्मजीवों की छिपी हुई क्षमता को बड़े पैमाने पर सामने लाया जा सकेगा। अनुक्रमण आंकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न महत्वपूर्ण एंजाइमों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जैव सक्रिय यौगिकों आदि के लिए जीनोम एन्कोडेड क्षमताओं की पहचान की जा सकती है। इस क्षेत्र में अनुसंधान से हमारे पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन, कृषि में विकास और मानव स्वास्थ्य में सुधार का लाभ मिलेगा।

इस पहल का समन्वय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद और राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (ब्रिक-एनआईबीएमजी) द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश में पृथक किए गए पूर्ण रूप से एनोटेट जीवाणु जीनोम को जन सामान्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है। इसे विस्तृत ग्राफिकल सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम असेंबली /एनोटेशन विवरण के साथ पूरक किया जाएगा।

शोध संबंधी ये दस्तावेज सूक्ष्मजीवों के वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग के बारे में एक विचार देंगे जिससे, माइक्रोबियल जीनोमिक्स से जुड़े आंकड़े जन सामान्य और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे और इस विषय पर शोध संबंधी चर्चाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इनसे संबंधित नवाचारों से देश और वैज्ञानिक समुदाय को लाभ होगा।

निगरानी समिति दिशा की बैठक 21 को

कांकेर। लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग की अध्यक्षता में 21 नवम्बर 2024 दिन गुरूवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक आयोजित की गई है। उसके पर्यवेक्षण संबंधी कार्यवाही पर चर्चा एवं समीक्षा की जाएगी।

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेन्ट्स
जींस, शर्ट, टी-शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैंसी सलवार सूट एवं किट्स वियर,अंडर गारमेन्ट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन
एक बार अवश्य पधारें
गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

Ashok
JEWELLERY
Gifts ● Toys ● Cosmetics
Perfumes ● Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

खास खबर

साइबर जागरूकता अभियान : धान बेचने वाले किसानों को किया जा रहा है जागरूक

बलौदाबाजार (ए.)। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के द्वारा पूरे जिले में जागरुकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी के बारे जागरूक कर रही है। जिले वासियों को साइबर अपराधियों द्वारा फेक कस्टमर केयर नंबर आदि के माध्यम से लोगों को ठगी से बचने के तरीके बताए।

साथ ही बताया कि अभी जानकारी मंडियों में धान का सीजन चल रहा है किसान धान बेचने के बाद भुगतान को लेने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, उन्होंने किसानों को आगाह करते हुए अपील की है, कि जब भी पैसा लेने बैंक जाए किसी भी अनजान व्यक्ति या लोगों पर भरोसा ना करें जितनी आवश्यकता हो उतने ही पैसे निकाले किसी भी प्रकार की ठगी होने पर तत्काल ही स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाए। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि लोग झूठे प्रलोभन से बचें। यदि इसके बावजूद साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्प लाईन नंबर 1930 पर काल करें।

कार की टक्कर से 4 लोग घायल

रायपुर। रायपुर के एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्विफ्ट डिजायर कार को

अज्ञात कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों को मेकाहारा अस्पताल भेजा गया है। जहां उनका इलाज जारी है। घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है।

मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर के एक्सप्रेस वे पर स्विफ्ट डिजायर कार को अज्ञात कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड निवासी शिवा मातेह नामक युवक परिवार सहित घायल हो गया। सभी घायलों को मेकाहारा अस्पताल भेजा गया है जहां पर उनका इलाज जारी है।

वहीं रायपुर के सत्ती बाजार इलाके में तड़के एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी। इसके बाद इलाके की बिजली गुल हो गई। कार ने स्टेशनरी दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मॉर्निंग वाक कर रहे स्थानीय लोग बाल-बाल बचे। कार चालक मौके पर से फरार हो गया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

यश राठी की हेट स्पीच के बाद आईआईटी भिलाई में बवाल, एनएसयूआई व करणी सेना का प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। आईआईटी भिलाई (IIT Bhilai) में एनुअल फंक्शन में स्टैंडअप कॉमेडियन यश राठी के प्रोग्राम के बाद बवाल शुरू हो गया है। यश राठी के हेट स्पीच का वीडियो वायरल होने के बाद आईआईटी प्रबंधन व कार्यक्रम आयोजित करने वाले लेपेट में आ गए हैं। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि सोमवार को एनएसयूआई व करणी सेना के कार्यकर्ता आईआईटी भिलाई के गेट पर प्रदर्शन करने लगे। इसकी सूचना मिलने के बाद एएसपी सुखनंदन राठौर, अभिषेक झा व सीएसपी चिराग जैन दल बल के साथ पहुंचे और मामला शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों ही संगठनों ने पुलिस को अपना अपना ज्ञापन सौंपा।

दरअसल यह पूरा बवाल एक वायरल वीडियो के कारण हुआ। यह वीडियो आईआईटी भिलाई में 9 नवंबर को हुए एनुअल फंक्शन का था। यहां हर साल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन कर एनुअल फंक्शन कराते हैं। इस वर्ष मेराज नाम से एनुअल फंक्शन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी की काउंसिल ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर नाम की कमेटी द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में समिति ने यश राठी को बुलाया और उसी कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में यश राठी को अश्लील व गंदी बाते करते देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में आईआईटी के प्रोफेसर्स से लेकर गर्ल्स स्टूडेंट्स व पैरेंट्स भी मौजूद थे। अश्लील व गंदी बातें सुनने लायक नहीं थी और प्रोफेसर्स को कान तक बंद करने पड़ गए।

एनएसयुआई व करणी सेना ने किया प्रदर्शन

आईआईटी भिलाई में यश राठी के हेट स्पीच वाले कार्यक्रम की चौतरफा आलोचना हो रही है। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में एक ऐसे शख्स का कार्यक्रम कराना जो कि अपनी हेट स्पीच के लिए चर्चित है। यश राठी के इस कार्यक्रम क वीडियो वायरल होने के बाद एनएसयूआई व करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी भिलाई का घेराव कर दिया। यश राठी का कार्यक्रम कराने वालों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर बाद एएसपी सुखनंदन राठौर, अभिषेक झा व सीएसपी चिराग जैन दल बल के साथ पहुंचे और प्रदर्शन को शांत कराने का प्रयास किया। एनएसयूआई व करणी सेना ने कार्रवाई को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।

जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित

यश राठी के कार्यक्रम के बाद मचे बवाल ने आईआईटी प्रबंधन के भी कान खड़े कर दिए हैं। इस कार्यक्रम के बाद आईआईटी भिलाई (IIT Bhilai) के डायरेक्टर राजीव प्रकाश का कहना है यश राठी के कार्यक्रम के कारण संस्थान की गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं। डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गेस्ट को बुलाया क्यों गया जो कि हेट स्पीच के मशहूर है इसकी जांच की जाएगी।

रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी, शातिर ने ट्रेनिंग के नाम पर गिनवाए रेल के डिब्बे, आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

पेंड्रा। मरवाही पुलिस को ठगी के एक मास्टरमाइंड आरोपी युवक को पकडने में सफलता मिली है, महज आठवीं फेल इस आरोपी युवक ने इंजीनियरिंग और बीए पास बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी किया और फिर ट्रेनिंग के नाम पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में ले जाकर झांसे में आए युवकों से रेल के डब्बे गिनवाता था।

थाना मरवाही और साइबर सेल जीपीएम ने गिरोह के मुख्य सरगना कपिल बरनवाल को आसनसोल बंगाल से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के थाना मरवाही क्षेत्र के ग्राम कुम्हारी के पुनीत प्रधान से रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की गई थी जो रकम अलग अलग किश्तों में आसनसोल में चली 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान ली गई थी। जब ठगी का पता चला तो प्रार्थी के होश उड़ गए क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का हर किरदार फर्जी निकला।

ठगी का अहसास होते ही पुनीत ने पुलिस से संपर्क कर थाना मरवाही में अपराध दर्ज कराया था। मरवाही पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से पूर्व में भी तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें एक युवक अमित मंडल ट्रेनिंग देता था तो विधान बैरागी और योगेश रजक स्थानीय स्तर पर युवाओं को झांसा देकर आसनसोल भेजते थे। इनका सरगना कपिल बरनवाल फरार था और लोकेशन बदल रहा था जैसे ही मुख्य आरोपी आसनसोल आया मरवाही पुलिस को जानकारी मिली जिस पर आसनसोल पुलिस के इंस्पेक्टर कौशिक कुंडू की सहायता से उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल सहायक उप निरीक्षक मनोज हनोतिया और प्रधान आरक्षक अजय सिंह ने आसनसोल में कपिल बरनवाल को गिरफ्तार किया।

आरोपी कपिल आसनसोल में भी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर घूमने के प्रकरण में जमानत पर था। मरवाही पुलिस ने आरोपी की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे मरवाही ले जाकर पुलिस रिमांड पर रखा था। डीएसपी साइबर दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी रणछोड़ सिंह सेंगर, उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल और साइबर सेल सउनि मनोज हनोतिया द्वारा पूछताछ और तफ़्तीश करने पर पता चला कि आरोपी कपिल बरनवाल की पत्नी पूजा हलदर मेकअप आर्टिस्ट हैं जिसके जरिए कई लोगों से कपिल के संपर्क हैं जो उसके लिए ठगी करने में अलग अलग किरदार निभाते थे। कभी कोई आरपीएफ वाला बन जाता तो कोई स्वास्थ्यकर्मी। पूछताछ में आरोपी कपिल ने बताया कि वह आठवीं फेल है और वह यह सब कुछ लक्जरी लाइफ जीने के लिए किया करता था। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका और नाम पते के बारे में मिली जानकारी के आधार पर कार्यवाही जारी है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक मनोज हनोतिया और प्रधान आरक्षक अजय सिंह मुख्य भूमिका में रहे।

छत्तीसगढ़ में अनोखी चोरी गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर अंडरगारमेंट चुरा रहा था बदमाश

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अनोखी चोरी : गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर अंडरगारमेंट चुरा रहा था बदमाश, पुलिस ने पहुंचकर पकड़ा

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। यहां एक युवक रविवार को आधीरात गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचा और एक कमरे में घुसकर लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराने लगा। लड़कियों ने विरोध किया तो उसने हमला करने की कोशिश की। इसके बाद लड़कियों की चीख निकल गई। आनन फानन में बात पुलिस तक पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला जीएनएम इंस्टीट्यूट के गर्ल्स हॉस्टल का है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक रविवार रात करीब 12 बजे छत से कूदकर जीएनएम इंस्टीट्यूट के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचा था। हॉस्टल में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली करीब 85 छात्राएं मौजूद थीं। युवक नशे की हालत में था और एक-एक करके हॉस्टल के कमरों के दरवाजे खटखटाने लगा। इससे हॉस्टल में मौजूद छात्राएं डर गई और चिल्लाने लगी। इस दौरान युवक एक कमरे घुस गया और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स उठाने लगा। लड़कियों ने विरोध किया तो उसने हमला कर दिया जिससे कुछ लड़कियों को चोट भी लगी है।

घटना की सूचना मिलने पर कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान राहुल नेम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि राहुल नेम नशे की हालत में था। जब पुलिस बदमाश को ले जा रही थी तो उसने दोबारा आने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना के बाद छात्राओं के परिजनों ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इंस्टीट्यूट की प्राचार्य ने बताया कि वार्डन एक दिन की छुट्टी पर गई है और उसकी जगह दूसरी वार्डन को अटैच किया गया। हालांकि घटना के समय हॉस्टल में वार्डन मौजूद नहीं थी। फ्लिहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट

स्टील कंपनी के निदेशक के बेटे व बहू को डिप्टी कलेक्टर बनाने ली थी 45 लाख की रिश्वत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष टोमन सिंह सोनवानी को रायपुर स्थित एक स्टील कंपनी के निदेशक से 45 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गोयल ने ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से 20 और 25 लाख रुपये की दो किस्तों में रिश्वत का भुगतान किया था। सोनवानी के रिश्तेदार ग्रामीण विकास समिति के सदस्य थे। आरोप है कि गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए रिश्वत दी गई थी।

बता दें 11 मई 2023 को सीजीपीएससी 2021 का अंतिम परिणाम जारी किया गया था। इसमें 15 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए थे। इनमें शशांक गोयल ने तीसरा और भूमिका कटियार ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। इस सूची में 15 अभ्यर्थियों का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ था। संदिग्ध परिणामों के बाद इस मामले की जांच की मांग उठाई गई थी। आरोप था कि मेरिट सूची में पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का फर्जी तरीके से चयन किया गया था। आरोपों के बाद भी पूर्व सरकार ने इसकी जांच नहीं कराई। फिर इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- कड़ी सजा मिलेगी

सीबीआई की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरा छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप सभी मन लगा कर पढ़ाई करें और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

हाईकोर्ट के आदेश पर रुकी नियुक्तियां

ननकी राम कंवर की याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोकने के आदेश दिए थे। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद यह मामला आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी थी और बाद में सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया। इसके बाद भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में सोमवार को टोमन सिंह सोनवानी व स्टील कारोबारी श्रवण गोयल की गिरफ्तारी हुई है।

पत्नी ने कुल्हाड़ी मारकर की पति की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आरोपिया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चरित्र पर शक व बार बार की प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला ने अपने की हत्या कर दी। रात को सोने के बाद सुबह विवाद हुआ और फिर पत्नी ने यह कांड कर दिया। हत्या के बाद पत्नी मेला देखने चली गई। घटना की सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ शव पड़ा था। शव को पीएम के लिए भेजने के बाद मामले में पुलिस ने आरोपिया पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के लैलूंगा थाना का है।

मृतक के चचेरे भाई सेतराम राउत ने पुलिस को बताया कि ग्राम पहाड़लुडेग निवासी निलांबर यादव (28) ने आठ साल पहले तिलासो माझी को पत्नी बनाकर घर लाया था। दोनों का चार साल का बेटा भी है। घटना के दिन गांव में कार्तिकेश्वर मेला था, जहां परिवार के अन्य सदस्य गए थे। सुबह निलांबर की हत्या की सूचना मिलने पर घर पहुंचे तो शव खाट पर पड़ा मिला। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। लैलूंगा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जांच तेज की।

घटनास्थल की गहन पड़ताल और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाए गए। पूछताछ के दौरान पत्नी तिलासो माझी पर शक गहराया। कड़ी पूछताछ में तिलासो ने बताया कि उसने 16 नवंबर को भोर में अपने पति निलांबर यादव की हत्या की। आरोपी महिला ने बताया कि मेला देखने के बाद रात तीन बजे वह घर लौटी और पति के साथ सो गई। सुबह जब वह दोबारा मेला जाने की तैयारी कर रही थी तो दोनों में झगड़ा हुआ। पति नीलाबंर बार बार पत्नी के चरित्र को बाते कर रहा था। चरित्र शंका और प्रताड़ना से परेशान होकर उसने घर में रखी टांगी से निलांबर के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हाथियों का दल पहुंचा बैगा बाहुल्य क्षेत्र, दहशत का माहौल

कवर्धा। चार हाथियों का दल बैगा बाहुल्य क्षेत्र तेलियापानी पहुंचा, लेदरा दादर और भेलकी गांव में हाथियों का झुण्ड देखने को मिला है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने गांव में मुनादी कराई और लोगों को देर रात घर से न निकलने की नसीहत दी गई। चार हाथियों का दल अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व क्षेत्र से विचरण करते पहुँचा, पूर्व में हाथियों के दल ने घरों में खूब उतपात मचाया था।

बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में बड़ा निर्णय

पर्यटन को बढ़ावा देने बस्तर में बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर श्री साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर एप्प लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पॉवर बैंक का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री साय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धूड़मारास गांव के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिली है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री साय ने प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित किया है। इन क्षेत्रों के विकास में आदिवासी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। सीएसआर मद में भी काफी राशि उपलब्ध है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केन्द्र और राज्य दोनों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए संवेदनशील सरकारें हैं।

बैठक में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सहित बस्तर सांसद महेश कश्यप और बस्तर संभाग के समस्त विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, सदस्य सचिव प्राधिकरण डॉ बसवराजु एस, विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर बस्तर, आईजी, सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बैठक में उपस्थित थे।

मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नियद नेल्लानार जैसी योजना और बस्तर ओलंपिक का आयोजन मुख्यमंत्री के विकास की पहल को दर्शाता है। वन मंत्री केदार कश्यप ने मत्स्यपालन, डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नदी किनारे विद्युत लाईन बिछाने, अटल व्यावसायिक परिसर, एफ्क्षारए क्लस्टर में सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ऐसे में बस्तर में नई खेल अकादमियों की स्थापना के लिए पहल की जाए।

पोटा केबिन को स्थायी बनाने का सुझाव

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, ऑर्गेनिक, नैचुरल फॉर्मिंग प्रारंभ करने पोटा केबिन को स्थायी बनाने का सुझाव दिया। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी ने बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, उद्यमिता के विकास के लिए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने प्रत्येक गांव में कृषि सेवा केंद्र प्रारंभ करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर स्थापित करने पर भी बल दिया। विधायक श्री किरणदेव सिंह ने कहा कि शोधार्थी छात्रों को सुविधाएं देने सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटल लैबोरेटरी की स्थापना की जाए।

आकांक्षी जिलों में अभियान चलाकर रिक्त पदों की भर्ती

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को पहुंचाने 95 गांवों में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने आकांक्षी जिलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिला प्रशासन को अभियान चलाकर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कांकेर कलेक्टर ने बैठक में बताया कि रावघाट परियोजना के तहत प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। बीएसपी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के 153 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सचिव शिक्षा ने बताया कि बस्तर अंचल में एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। उन्होंने भवनविहीन स्कूलों के लिए भवन का प्रावधान करने की जानकारी दी।

2026 तक माओवादी आतंक खत्म करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवादी आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में राज्य में बेहतर काम हो रहा है। माओवादी आतंकवाद छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। हम लोगों ने बस्तर में पूर्ण शांति बहाली करते हुए अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। यह तभी होगा जब शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। यह विश्वास विकास से ही निर्मित होगा।

नियद नेल्ला नार योजना से मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टॉवर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत 34 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं जहां ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बस्तर में शांति कायम हो, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सतत प्रयास कर रही हैं। बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से अमूल्य सुझाव मिले। सभी टीम भावना से काम करके विकास के प्रति एकजुटता दिखाएं।

केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने और प्राधिकरण मद से स्वीकृत सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने निर्देशित किया। उन्होंने कलेक्टर बस्तर को देवगुड़ी, मातागुडी के अप्रारंभ कार्यों को डेढ़ महीने में पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने दंतेवाड़ा के ग्राम नेरली, धुरली में लाल पानी की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एनएमडीसी को समाधानकारक उपाय करने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त बैठक कर आवश्यक पहल करें।

मुख्यमंत्री साय का बस्तरिया अंदाज में हुआ स्वागत, गौरसिंग मुकुट पहनाकर किया अभिनन्दन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने चित्रकोट पहुंचने पर बस्तरिया अंदाज में स्वागत हुआ। उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक गौर सिंग मुकुट पहनाकर उनका अभिनन्दन किया।

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के आयोजन हेतु विशेष तैयारियां की गई थीं7 इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न विभागीय स्टालों का अवलोकन किया। प्राधिकरण की बैठक स्थल पर संभाग के सात जिलों बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को स्टॉल के जरिए साझा किया। इन स्टालों में विकास और नवाचार की विस्तृत झलक दिखी।

'बस्तर कॉफी' के सफर की दिखी झलक

बस्तर जिले के स्टाल में 'बस्तर कॉफी' की प्रक्रिया और उसके प्रसार को रोचक ढंग से दिखाया गया है। प्रदर्शनी में कॉफी उत्पादन, ताजा चेरी उत्पादन से लेकर कॉफी की धुलाई, भुनाई, पिसाई और पाउडर पैकेजिंग तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है। 'बस्तर कैफे' की पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। बस्तर कॉफी ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास भी जारी है।

कला और नवाचार का संगम

कोण्डागांव जिले ने स्टाल के माध्यम से अपनी पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक विकास परियोजनाओं को सामने रखा है। झिटकू मिटकी आर्टिसन प्रोड्यूसर ने बेल मेटल कला से अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्थापत्य को प्रदर्शित किया। इस दौरान जिले में हो रहे पर्यटन विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने गारमेंट फैक्ट्री, एनीमिया मुक्त कोण्डागांव अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, 'मावा कोण्डानार' मोबाइल ऐप: पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जानकारी दी गई।

शिक्षा और बाल विकास में नवाचार

दंतेवाड़ा जिले ने शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में किए गए नवाचारों को साझा किया। बाल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल से बाहर और अप्रवेशी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल शुरू की गई है । बाल मित्र पुस्तकालय एवं पंचायत के जरिए बच्चों को नेतृत्व और निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ समग्र विकास के लिए भी अहम साबित हो रहा है।

लघु वनोपज से बढ़ती आजीविका

कांकेर जिले में लघुवनोपज आधारित परियोजनाओं और उद्यानिकी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रेश सीताफल परियोजना के तहत स्थानीय किसानों सहित स्वसहायता समूह की दीदियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत बनी है। पोषण और रोजगार, लघु धान के मछली पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन में रोजगार के नए अवसर और आजीविका संवर्धन की जानकारी दी।

महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

नारायणपुर जिले ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं।सहायता समूहों की दीदियों ने हर्बल गुलाल, मशरूम उत्पादन, कड़कनाथ पालन और बटेर पालन जैसी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। इन गतिविधियों से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है।पोषण आहार और एकीकृत कृषि, कृषि में नवीन तकनीकों के समावेश का प्रदर्शन किया गया है।

यातायात और आवासीय योजनाओं की प्रगति

सुकमा जिले के स्टाल में आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। हक्कुम मेल अंतर्गत यातायात सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में हो रही कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना,आवासीय परियोजनाओं ने सकारात्मक बदलाव के संबंध सहित लखपति दीदी योजना मरईगुड़ा पंचायत सहित, महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण में हो रही सकारात्मक परिणामों को किया गया।

'नियद नेल्ला नार' योजना के सकारात्मक परिणाम

बीजापुर जिले में प्रदेश सरकार द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित 'नियद नेल्ला नार' योजना के माध्यम से समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ग्रामीणों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए तकनीकी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जिले के प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटन के माध्यम से दुनिया के पटल पर रखने के प्रयासों की जानकारी दी गई है।

आदिवासी अँचलों में 77,292 घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य प्रगति पर

मुख्यमंत्री साय ने 426 करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आदिवासी अँचलों में बिजली से वंचित रह गए घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 3 अतिविशिष्ट योजनाओं के माध्यम से 77,292 घरों में बिजली पहुंचाने की कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा इस महती कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है जिसमें से 2 योजनाएं केंद्र सरकार की है तथा 1 योजना छत्तीसगढ़ शासन की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 426 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए है।

वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष रोहित यादव ने तीनों योजनाओं की प्रगति की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की अति पिछड़ी 7 जनजातियों जिनमें अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरवा, कमार तथा बिरहोर शामिल हैं, इन 7 जनजातियों के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रिड से विद्युतीकृत गांवों के 7,077 घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 37 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1,087 बसाहटों में 363.24 किलोमीटर 11 के.वी. लाइन, 267 नग 25 के.वी.ए. क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर तथा 650 किलोमीटर से अधिक निम्नदाब लाइनें बिछाई जा रही है। पीएम जनमन के तहत अभी तक 4,500 घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा हाल ही में की गई है जिसके अंतर्गत 919 गांवों के 65,711 अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 323 करोड़ 63 लाख रुपए की कार्ययोजना को स्वीकृति मिली है। जिसके अंतर्गत 6,863 बसाहटों में 1889.56 किलोमीटर लाइनें, 25 के.वी.ए. क्षमता के 1950 वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जाएंगे तथा 5,188 किलोमीटर से अधिक निम्नदाब लाइनें बिछाई जाएंगी।

आदिवासी बहुल गांवों में बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या वहां के सघन वन क्षेत्र होते हैं। घने जंगलों में बहुत से क्षेत्र पहुंच विहीन होती हैं। इसके अलावा बस्तर के सघन वन क्षेत्रों में विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्या भी है जिसके समाधान की दिशा में राज्य सरकार द्वारा केंद्र की मदद से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मोर्चे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सुरक्षाबलों की तैनाती केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा की गई है। जिसके लिए सुरक्षा कैम्प बनाए गए है। सुरक्षा कैम्पों के समीप 5 किलोमीटर के दायरे में बहु-आयामी विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा नियद नेल्लानार योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के अंतर्गत 24 सुरक्षा कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में 96 गांवों में घरों को रोशन करने की कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें ग्रिड से विद्युतीकृत 8 गांवों के 105 आवासों तथा ऑफग्रिड विद्युतीकृत 61 गांवों के 4,399 आवासों को ग्रिड से विद्युतीकृत करने की योजना प्रचलन में है। 61 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के अंतर्गत उपकेंद्रों, वितरण लाइनों की स्थापना की जा रही है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950